दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर व उत्तर प्रदेश से एक साथ प्रसारित

विशेष खबर

खबरों पर गहरी नजर

पेज-6 रिकार्ड जीत हासिल कर गाजियाबाद की प्रथम महिला बनी सुनीता दयाल

Follow us on @VisheshKhabartv www.visheshkhabar.in @visheshkhabar6115 9711345310

वर्षः 6 अंकः 2 हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र गाजियाबाद, सोमवार 15 मई 2023 visheshkhabar.tv@gmail.com RNI NO :UPHIN/2017/74151 पृष्ठः 6 मूल्यः 5 रूपये

अन्दर के पेजों पर
2 संपादकीयः हिन्दूत्व और मोदी की परछाई से कब बाहर निकलेगी भाजपा
4 दिल्ली में पॉवर गेम की लड़ाई फिर अदालती चक्रव्यूह में फंसी
5 जिले में बसपा-सपा की जगह केजरीवाल और औवेसी बन रहे मुस्लिमों की पसंद
6 यूपी में आंधी थी पर मेरठ-सहारनपुर मंडल में 26 पालिका में ही खिला कमल

खास खबरें

हैरानी

रामजन्म भूमि से सटे वार्ड में हिन्दू बहुल सीट पर जीत गया एक निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार

संवाददाता @visheshkhabar.in

अयोध्या। अयोध्या में संत अभिराम दास के नाम पर बने वार्ड से जीता मुस्लिम प्रत्याशी, तीसरे नंबर पर रही इखढ

यूपी निकाय चुनाव 2023 के रिजल्ट जारी हो गए हैं। बीजेपी को इस चुनाव में बंपर जीत मिली है। बीजेपी ने मेयर की सभी 17 सीटों पर चुनाव जीत लिया है। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि सपा और बसपा को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं इस चुनाव में कुछ निर्दलीयों ने भी सभी प्रमुख पार्टियों को चौंका कर नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद की सीट पर कब्जा किया है।

इन्हीं सीटों में से एक सीट अधोध्या जिले की है, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहां राम अभिराम दास वार्ड से एक मुस्लिम प्रत्याशी सुल्तान अंसारी ने जीत हासिल की। खास बात यह है कि इस वार्ड में सबसे ज्यादा हिंदू वोटर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव बड़े अंतर से जीत लिया।

बता दें कि राम अभिराम दास वार्ड का नाम राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले महंत अभिराम दास के नाम पर पड़ा था। यह वार्ड राम जन्मभूमि ठीक पीछे स्थित है। इस वार्ड में मुस्लिम वोट शेयर कुल वोटों का मात्र 11 प्रतिशत ही है, लेकिन उसके बावजूद निर्दलीय सुल्तान अंसारी यहां से चुनाव जीत गए. राम अभिराम दास वार्ड में 440 मुस्लिम वोट हैं, जबकि 3,844 हिंदू वोट हैं।

इस वार्ड से कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। वोटिंग वाले दिन 2,388 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुल्तान अंसारी को सबसे ज्यादा 996 यानि 42 प्रतिशत वोट मिले। दूसरे स्थान पर भी यहां एक निर्दलीय उम्मीदवार रहा। सुल्तान अंसारी ने अपने प्रतिद्वंदी नागेंद्र मांझी को 442 वोटों के अंतर से हराया। इस वार्ड में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। जीत के बाद सुल्तान अंसारी ने कहा कि वह युवा हैं और वार्ड के लोगों ने उन पर भरोसा जताया। यहां चुनाव में हिंदू-मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं रहा। सिर्फ विकास ही हमारा मुद्दा रहा। सुल्तान अंसारी ने कहा कि यहां हिंदू-मुस्लिम भाईचारा है. हम लोग शांति प्रिय लोग हैं. न हमें पक्षपात करना आता है और न ही हमारे हिंदू भाइयों को। मेरी जीत बताती है कि हिंदू भाइयों ने मुझे किसी धर्म विशेष का नहीं, बल्कि अपने बीच का माना और मेरा समर्थन किया।

कर्नाटक में आप का अनोखा रिकार्ड

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया। इससे उत्साहित केजरीवाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 209 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम से आप पार्टी फिसड्डी ही साबित हुई। यहां केजरीवाल ने फ्री बिजली और किसानों के लोन माफ करने जैसे रेवड़ी का लालच भी लोगों को दिया लेकिन रेवड़ी कल्चर भी काम नहीं आई। आप के नाम सभी 209 विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड कायम हो गया। इसके साथ ही वह देश की कुछ उन पार्टियों के क्लब में शामिल हो गई जिसने बड़ी संख्या में जमानत जब्त करवाई हो। इसके साथ ही आप के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया, उसे कर्नाटक चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले। कर्नाटक चुनाव में नोटा के तहत 0.69 प्रतिशत वोट डाले गए वहीं आप को कुल 0.58 प्रतिशत वोट मिले।

यूपी में जीत की कहानी कार्टून की जुबानी

कांग्रेस ने बीजेपी से छीना कर्नाटक का इकलौता दुर्ग

शिवकुमार गांधी परिवार की पसंद, सिद्धा ने फंसाया पेंच

विधायकों से रायशुमारी– डी के शिवकुमार या सिद्धारम्मैया

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

बंगलुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार भी दशकों से चला आ रहा रिवाज कायम रहा। बीजेपी एड़ी-चोटी के जोर के बावजूद भी इस ट्रेंड को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को करारी मात देकर पूर्ण बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की है। शुरूआती रुझान में ही कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते बहुमत का आंकड़ा भी पार कर गई। दरअसल, 1985 से आज तक कर्नाटक में कोई भी सत्तारूढ़ दल दोबारा से सत्ता पर काबिज नहीं हो पाया है।

कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं, बीजेपी के लिए ये लोकसभा चुनाव 2024 से पहले निश्चित तौर पर बड़ा झटका है। कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार जीत के बाद भावुक होते हुए कहा कि मैं अपने कार्यकताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय देता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। मैं भूल नहीं सकता, जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी।

कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के बाद अब कांग्रेस को फैसला करना है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए? इसके लिए पार्टी के विधायक दल की बैठक बेंगलुरु के शांगरी-ला होटल में चल रही है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के साथ 3 ऑब्जर्वर सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तय किया गया कि विधायक दल का नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे। सिद्धारमैया ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसका शिवकुमार समेत सभी विधायकों ने समर्थन किया।

इधर, मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर ऑब्जर्वर्स ने सभी विधायकों से वन-टु-वन बात करना शुरू कर दिया है। बैठक के दौरान शिवकुमार-सिद्धारमैया के समर्थक होटल के बाहर नारेबाजी करते रहे।

बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस सांसद व नेता के. सी. वेणूगोपाल का कहना है कि विधायकों की राय लेने की प्रक्रिया रात में पूरी कर ली जाएगी। ये एक सर्वसम्मत प्रस्ताव है जिसे सिद्धारमैया ने पेश किया और डी.के. शिवकुमार सहित सभी सीनियर लीडर्स की ओर से इसका समर्थन किया गया।

हांलाकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि सीएम कौन बनेगा लेकिन अगर सबकुछ ठीक रहा तो कांग्रेस राज्य के नए मुख्यमंत्री के शपथग्रहण का कार्यक्रम 18 मई का आयोजित कर सकती है।

सिद्धारमैया के फार्मूले से फंस गया सीएम का पेंच

कर्नाटक में मुख्यमंत्री चयन को लेकर जो कुछ भी चल रहा वो पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया हो सकती है। विधायकों ने भी भले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर नए मुख्यमंत्री को चुनने का अधिकार दे दिया हो, लेकिन पर्दे के पीछे का सच ये हैं कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी डी के शिवकुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये बात खरगे से लेकर सभी आब्जर्वर को भी बता दी गई है। अब बस इंतजार है कि सभी विधायक तीनों आब्जर्वर को अपनी राय बता दें । इसके बाद आब्जर्वर पार्टी अध्यक्ष खरगे को इससे अवगत करा देंगे। अगर विधायकों की राय शिवकुमार के पच में रही तो खरगे खुद उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो खरगे सोनिया व राहुल से विचार विमर्श कर इसका फैंसला लेंगे। दोनों ही स्थितियों में डी के शिवकुमार ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे देखना है इसमें कितना समय लगेगा। हांलाकि सिद्धारमैया ने पहले दो साल खुद को उसके बाद डीके को सीएम बनाने का फार्मूला दिया ह% जिसके बाद सीएम पद को लेकर पेंच पफंस सकता हैं। सोमवार को गांधी परिवार से दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद स्थिति साफ होगी।

निकाय चुनाव: योगी के रंग में रंगा उत्तर प्रदेश

17 मेयर, 96 पालिका अध्यक्ष और 196 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर कब्जा

▶ हर चुनाव में गिरता जा रहा है सपा बसपा की सफलता का ग्राफ

मनोज गौड @visheshkhabar.in

लखनऊ । नगर निकाय चुनाव में पूरा यूपी योगीमय हो गया। यूपी के 17 नगर निगम सीटों पर भगवा लहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारथी की भूमिका में यूपी की सभी 17 नगर निगम सीटों पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की थी। सीएम योगी के कार्यों का परिणाम ही है पिछली बार हारी मेरठ व अलीगढ़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। वहीं पहली बार बने शाहजहांपुर में भी कमल ने कमाल कर दिया। यहां भी पहला नागरिक बनने का गौरव भाजपा उम्मीदवार अर्चना वर्मा को मिला।

17 में से 17 पर निगम में कमल

भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की सभी 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से कानपुर, बरेली व मुरादाबाद में भाजपा ने निवर्तमान महापौर पर ही दांव लगाया था, शेष सभी सीटों पर नए कार्यकताओं को चुनाव मैदान में उतारा था। 17 में से 17 सीटों पर योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों पर आमजन ने मुहर लगाई और कमल खिलाया।

भाजपा के साथ से प्रमिला, विनोद, हरिकांत व उमेश दोबारा बने महापौर

भारतीय जनता पार्टी और योगी के प्रति आमजन का विश्वास है कि पार्टी के चार प्रत्याशियों ने दूसरी बार महापौर बनने का गौरव हासिल किया। कानपुर से प्रमिला पांडेय, मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल और बरेली से उमेश गौतम अनवरत दूसरी बार महापौर बने, जबकि हरिकांत अहलूवालिया इसके पहले भी मेरठ के महापौर रह चुके हैं। झांसी में के बिहारी लाल ने सबसे पहले जीत हासिल की। उन्हें कुल 123503 वोट मिले। वहां लड़ने वाले अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई।

योगी आदित्यनाथ ने की थी 50 रैली

सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में कुल 50 रैलियां कीं। योगी आदित्यनाथ ने यहां सीएम योगी ने 9 मंडल के अंतर्गत आने वाली 10 नगर निगम क्षेत्रों में रैली

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव परिणाम

	बीजेपी	बीएसपी	कांग्रेस	एसपी	अन्य
नगर निगम 17 / 17	17	0	0	0	0
नगर पंचायत 544 / 544	196	91	38	14	205
नगर पालिका 199 / 199	94	39	16	4	46

की। पहले चरण में योगी आदित्यनाथ की कुल 28 रैली हुई। इसमें गोरखपुर में 4, लखनऊ में 3 व वाराणसी में दो स्थानों पर रैली-सम्मेलन में योगी शामिल हुए। पहले चरण के 37 जिलों में 4 मई को मतदान हुआ। दूसरे चरण में सीएम योगी ने 22 रैलियां कीं। इसमें 9 मंडल की सात नगर निगमों के लिए वोट पड़े। यहां अयोध्या नगर निगम के लिए सीएम योगी दो बार पहुंचे। यहां संत सम्मेलन में भी सीएम की उपस्थिति जीत के लिए काफी कारगर रही।

साल दर साल बढ़ता गया योगी पर यकीन लगातार गिरता गया सपा बसपा का ग्राफ

यूपी के 25 करोड़ जनमानस का यकीन योगी पर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2017 में योगी के सत्ता संभालने के बाद से ही आमजन ने सूर्य की भांति योगी आदित्यनाथ के चमकने में भरपूर योगदान दिया। विधानसभा चुनाव हों, लोकसभा चुनाव हों या उपचुनाव, हर जगह भाजपा का पलड़ा भारी रहा। यह क्रम नगर निकाय चुनाव 2023 में भी जारी रहा। 2017 के मुकाबले 2023 में योगी आदित्यनाथ के विकास, कानून व्यवस्था व शहरी व्यवस्था के दृष्टिगत नगर निगम, नगर पंचायत व नगर पालिका में कमल ने कमाल कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ इतना गिरा कि पिछली बार जीती सीटों को भी बरकरार नहीं रख पाई।

निगम में 17 महापौर व 813 पार्षदों ने खिलाया कमल

योगी आदित्यनाथ के कार्य व चुनाव प्रचार की बदौलत इस बार नगर निगम में महापौर की सभी 17 सीटों पर कमल खिला, जबकि 2017 में 16 में से 14 पर ही भाजपा को जीत मिली थी। नगर निगम में पार्षदों की संख्या पर नजर डालें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के 1420 में से 813 जनप्रतिनिधि कमल खिलाने में सफल रहे। पिछली बार यह आंकड़ा 596 का था। शहरों में भाजपा की यह जीत योगी के विकास पर आमजन की मुहर है।

नगर पालिका के 88 अध्यक्ष और 1353 सदस्य

नगर पालिका में भी योगी का जादू खूब चला। योगी आदित्यनाथ ने नगर पालिका प्रत्याशियों के पक्ष में भी जनसभा कर वोट देने की अपील की। जनता ने इस अपील को न सिर्फ माना, बल्कि कई जगहों पर कमल के वोट प्रतिशत में भी खूब इजाफा किया। नगर पालिका परिषद के 60 अध्यक्ष पद पर 2017 में भाजपा को जीत मिली थी। 199 सीटों में से यह आंकड़ा इस बार बढ़कर 96 पहुंच गया। वहीं पालिका परिषद सदस्यों में पिछली बार भाजपा को 923 सीट मिली थी। 2023 में यह संख्या बढ़कर 1353 हो गई।

नगर पंचायतों में भी शतक से आगे पहुंची भाजपा

नगर पंचायतों में भी भाजपा ने परचम लहराया। 544में से 196 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर भाजपा के प्रतिनिधि काबिज हुए। 2017 में यह आंकड़ा सिर्फ 100 का था। यानी योगी के विकास की बदौलत न सिर्फ 91 और सीटें भाजपा की झोली में आईं, बल्कि वोट प्रतिशत में इजाफा भी खूब हुआ। भाजपा के नगर पंचायत सदस्यों की संख्या भी 664 से बढ़कर 1403 हो गई।

सपा की साइकिल पंचर, बसपा का हाथी भी सुस्त

नगर निगम, पंचायत व पालिका में सपा की साइकिल पंचर हो गई तो बसपा का हाथी भी गिर गया। 2017 की अपेक्षा इस चुनाव में इन दोनों प्रमुख विपक्षी दलों का हाल बहुत बुरा रहा। नगर निगम में सपा महापौर की रेस में शून्य पर ही रही। पार्षद 202 से घटकर 191 पर आ गए। नगर पालिका परिषद अध्यक्षों की संख्या भी 45 से घटकर 35 हो गई। 2017 में सपा सदस्यों की संख्या 477 थी, वह 2023 में 423 हो गई। 2017 में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा को 83 सीटों पर जीत मिली थी, 2023 में 78 पर सपा सिमट गई। बहुजन समाज पार्टी के दो महापौर 2017 में चुने गए थे। इस बार उनका खाता भी नहीं खुला। पार्षद 147 से घटकर 85 हो गए। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बसपा के 29 से 16 हो गए। पालिका परिषद सदस्यों की संख्या 262 से 191 हो गई। नगर पंचायत अध्यक्ष भी 45 से घटकर 37 और सदस्य 218 से घटकर 215 हो गए।

संपादकीय

परीक्षा के नतीजों में व्यवहारिक बेहतरी की शुरूआत

बीते शुक्रवार का दिन परीक्षा परिणामों के नाम रहा। यूं तो देश में परीक्षाएं हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षाओं और परिणामों का सबको खास तौर पर इंतजार रहता है। सीबीएसई ने शुक्रवार को पहले 12वीं और फिर 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। प्रतिभाशाली बच्चों की कोई सूची चर्चा में नहीं है, तो इससे कुल मिलाकर एक राहत का एहसास है। पहले जब मेरिट लिस्ट जारी होती थी, तब फेल होने वालों का अलग हाहाकार महसूस होता था। अब अगर 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम मेरिट के आतंक से बाहर निकल आए हैं, तो यह शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक और मानवीय तरक्की का ही संकेत है। कुल मिलाकर, एक समझदारी का माहौल नजर आ रहा है। कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती है, एक परीक्षा में शीर्ष पर आ जाने से कोई हमेशा के लिए सफल नहीं मान लिया जाता और न एक बार कम नंबर आने से कोई हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। पहले के समय में 10वीं बोर्ड रिजल्ट का सर्वाधिक महत्व होता था, लेकिन अब 12वीं बोर्ड का भी खूब महत्व हो गया है। कक्षा 10वीं के परिणाम के अनुसार, 93.12 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं, जबकि कक्षा 12वीं में 87.33 प्रतिशत को कामयाबी हासिल हुई है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के तहत देश भर में परीक्षा देने के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 21,84,117 थी, जबकि 21,65,805 ने ही परीक्षा दी और 20,16,779 विद्यार्थी पास हो गए हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि 18,312 छात्र परीक्षा में क्यों नहीं बैठे? यह एक शैक्षणिक-सामाजिक समीक्षा का विषय है। परीक्षा से बचे या वंचित रहे छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है।

भारत में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन जब परीक्षा परिणामों की चर्चा होती है, तब इन छात्रों को हम भूल जाते हैं। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकतम छात्र परीक्षा में बैठें और उत्तीर्ण हों। भारत जैसे देश में तमाम राज्य सरकारों के भी शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लगभग सारे योग्य विद्यार्थी कम से कम 10वीं तो पास करें। गौर करने का विषय है कि इस बार पास होने वालों का प्रतिशत घटा है। 12वीं की बात करें, तो इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.38 प्रतिशत कम है। साल 2022 में कुल पास प्रतिशत 92.71 था। इस वर्ष 10वीं कक्षा में पास होने वालों की संख्या भी 1.28 प्रतिशत कम है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह कोरोना महामारी के बाद हुई पहली सामान्य पूर्ण परीक्षा थी। लगभग दो साल बाद स्कूल लौटे छात्रों का प्रदर्शन कमतर होने की आशंका पहले से ही थी। हालांकि, इस मोर्चे पर शिक्षकों को भी अपने प्रदर्शन पर जरूर गौर करना चाहिए।

इस बार शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता भी इतनी ज्यादा दिख रही है कि चिंता स्वाभाविक है। मिसाल के लिए, दक्षिण भारत में राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 12वीं बोर्ड में उच्चतम प्रदर्शन त्रिवेंद्रम क्षेत्र ने किया है, जहां 99.91 विद्यार्थी सफल रहे हैं। बेंगलुरु में 98.64 प्रतिशत, चेन्नई में 97.40 प्रतिशत, जबकि प्रयागराज 78.05 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे दिख रहा है। उत्तर भारतीय राज्यों के स्कूलों के लिए संकेत स्पष्ट हैं। हमेशा की तरह इस बार भी 10वीं और 12वीं, दोनों में ही लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। खैर, अब महामारी का दौर गया, तय है, अगले साल परिणाम बहुत बेहतर आएंगे।

फिल्म पर प्रतिबंध क्यों ?

एक बार फिर किसी एक फिल्म को लेकर देश की राजनीति दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। मामला 'द केरल स्टोरी' का है जिसमें साजिशन धर्मांतरण करवाकर लड़कियों को आतंक के जाल में फंसाने का मुद्दा उठाया गया है। फिल्म में इस विषय को कितने अच्छे या बुरे ढंग से दिखाया गया है, यह एक अलग सवाल है। इसके चित्रण की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसकी तारीफ भी की जा रही है। इसमें उठाए गए मुद्दे की गंभीरता ने लोगों का ध्यान खींचा हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि फिल्म में काल्पनिक बातों को सच्ची घटनाओं पर आधारित बताते हुए पेश किया गया है, जिसका मकसद केरल के समाज को बदनाम करना है। ये आरोप-प्रत्यारोप और शिकवा-शिकायतें अपनी जगह हैं। देश में कानून का शासन है और उसका सम्मान सरकार तथा शासन-प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ सभी को करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी सरकारें भी अक्सर राजनीतिक हानि-लाभ की चिंता में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अधिकार क्षेत्रों और उनकी मान-मर्यादा का ख्याल छोड़ देती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का 'द केरल स्टोरी' को बैन करने का फैसला इसी श्रेणी में आता है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए आदेश जारी कर दिया कि राज्य के किसी भी सिनेमाघर में यह फिल्म प्रदर्शित नहीं की जाएगी। लेकिन यह फिल्म यूं ही सिनेमाघरों तक नहीं पहुंची है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने उचित प्रक्रिया के तहत उसका परीक्षण करने के बाद बाकायदा उसे ए सर्टिफिक्ट प्रदान किया है। उसके बाद भी फिल्म का प्रदर्शन रुकवाने के तमाम कानूनी प्रयास किए गए जो नाकाम रहे। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म का प्रदर्शन रोकने का अनुरोध ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में हाईकोर्ट को निर्देश देने की अपील खारिज कर चुका है। इस सबके बाद भी अगर कोई राज्य सरकार कहती है कि फिल्म दिखाए जाने से उसके यहां कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है तो सवाल उस राज्य में कानून-व्यवस्था वाली मशीनरी की कुशलता पर उठता है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह सेंसर बोर्ड से मंजूर की गई फिल्में देखने का अपने नागरिकों का अधिकार छिनने न दे। तमिलनाडु सरकार ने फिल्में न दिखाने का ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया, लेकिन वहां भी फिल्म प्रदर्शित नहीं हो सकी, जिसे बीजेपी राज्य सरकार की परोक्ष दादागीरी बता रही है। बहरहाल, दक्षिणपंथी दल और संगठन इस मामले में पहले से बदनाम रहे हैं। हर छोटे-बड़े मुद्दे को अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं का अपमान बताने का ट्रेंड हम हाल के वर्षों में देखते रहे हैं। अफसोस यह है कि खुद को लेफ्ट लिबरल दायरे में रखने वाले लोग भी कोई बेहतर उदाहरण नहीं पेश कर पा रहे। लेकिन हर शख्स जानता हैं कि इस पिफल्म में जो मुद्दा उठाया गया ह% वो एक ज्वलंत विषय है।

हिन्दूत्व और मोदी की परछाई से कब बाहर निकलेगी भाजपा

विनीतकांत पाराशर
प्रधान संपादक

कर्नाटक के नतीजों ने एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि हर बार तथा हर जगह का वोटर धर्म की राजनीति का साथ नहीं देता, साथ ही इस बात का भी संकेत हैं कि भाजपा जैसी बडी पार्टी को अब हिन्दूत्व तथा नरेन्द्र मोदी की छाया से बाहर आकर राजनीति करनी होगी वरना हिमाचल व कनार्टक जैसे नतीजों के लिए तैयार रहना होगा।

दृष्टिकोण

एक दौर था, जब भाजपा नेता बड़े गर्व तथा व्यंग्य से कहते थे कि राहुल गांधी जहां प्रचार करने जाते हैं, वहां हमारी जीत आसान हो जाती है, क्योंकि लसेग उनके कहने पर वोट नहीं डलते। अब जबकि कर्नाटक में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने जा रही है, तब यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पार्टी के दिग्गज नेताओं के बारे में भी सोची जानी चाहिए कि इस साल हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक के मतदाता ने भी उन के कहने पर भाजपा को वोट नहीं दिया।

मतदान के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर्नाटक में की, बजरंगबली तक का वास्ता दिया, कांग्रेस और गांधी नेहरु परिवार को बिना पानी पिए कोसा, लेकिन तमाम टोटके आजमाने के बाद भी वोटर ने न तो उन का भरोसा किया और न ही भाजपा का, तो यह इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनावों और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भगवा खेमे के लिए चिंता की बात है कि आखिर चूक कहां हो रही है।

चूक यह हो रही है कि भाजपा हर चुनाव में पूरी तरह मोदी और हिंदुत्व की राजनीति पर आश्रित हो गई है। कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बुराई भी पहले जैसी असरदार साबित नहीं हो रही, क्योंकि मतदाता 8 साल से लगातार एक ही बात सुन रहा है, जिस से उस के कान पक चुके हैं। शायद इसी पर प्रियंका गांधी का यह हमला अपील कर गया कि भाजपा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर ने के लिए गांधी परिवार व दूसे बेमतलब के मुद्दों को हवा दे रही हैं। शायद इसीलिए कर्नाटक की गृहणियों, युवाओं और किसानों ने बजरंगबली के नाम पर वोट नहीं किया, जैसा कि हिंदीभाषी राज्यों में आमतौर पर वोटर जज्बाती हो कर वोट फेंक आया करता है।

वैसे देखा जाए तो यह मानसिकता अब हिंदी भाषी राज्यों में भी दिखने लगी है। 4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के दिग्गज भाजपाई दीपक जोशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए. उन्होंने बेहद दुखी हो कर शिवराज सिंह सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा के जमीनी आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने भी ऐसा ही किया था।

लेकिन कर्नाटक में भाजपा के सत्ता में बाहर होने की एक बड़ी वजह ये रही कि स्थानीय मुद्दों को पूरी तरह दरकिनार कर भाजपा पीएम मोदी पर आश्रित हो गई। भाजपा के स्थानीय क्षत्रपों के यहां इतने गुट बन गए कि भाजपा के केन्द्रीय रणनीति कारों ने स्थानीय मुद्दो की जगह यहां भी उसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया जिसका प्रयोग वो तमाम हिन्दी भाषी राज्यों में करती रही है। यानि कांग्रेस का परिवार वाद, कांग्रेस काल में भ्रष्टाचार तथा हिन्दूत्व को लेकर कांग्रेस की सोच। शायद यहीं पर भाजपा से चूक हो गई।

केन्द्रीय नेतृत्व जब तक राज्यों में स्थानीय नेताओं को आगे बढाने की नीति पर काम नहीं करेगा तब तक मोदी पर भाजपा की निर्भरता खत्म नहीं होगी। लिंगायतों का दो फाड़ होना तथा क्षेत्रिय नेता येदियुरप्पा की अनदेखी भी भाजपा की हार की एक बडी वजह बनी। जिन के दम पर भाजपा कुरसी हथियाती रही थी। लेकिन येदि की नाराजगी के कारण यह सिलसिला भी खत्म हो गया।

असल में कांग्रेस ने इस चुनाव में बेहद चतुराई से काम लिया। उस ने हनुमान को हाईजैक करने में कोई लिहाज नहीं किया। जीत के बाद कर्नाटक में कांग्रेसी हनुमान का मुखौटा लगा कर घूमते दिखे और प्रियंका गांधी हिमाचल के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आईं। शनिवार हनुमान का दिन होता है और इसी दिन के नतीजे में भाजपा का सत्ता से बाहर होना यह बता गया कि हनुमान अगर कहीं हैं तो वे भाजपा से रुष्ट हैं, क्योंकि भगवा पार्टी का देशभर में हनुमान चालीसा का पाठ भी उन का दिल बहला नहीं पाया और उन की कृपा कांग्रेस पर बरसी।

अब जो भी होगा, सियासी घटनाएं और हमेशा की तरह होने वाली उठापटक होगी। मसलन, मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल कैसा होगा, लेकिन इक्लौती अहम बात और संदेश कर्नाटक से यह आया है कि धार्मिक मुद्दे और भटकाने वाले भाषण नहीं चलेंगें । आप को लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो 3 राज्यों में होने जा रहे चुनावों में भी नतीजे ऐसे ही मिलेंगे, जो घाव हिमाचल प्रदेश में मिले थे. कर्नाटक ने उस पर नमक छिड़क दिया गया है।

नज़रिया

संध्या सारस्वत
समाज सेविका, लेखिका
स्वतंत्र स्तंभकार

राजस्थान में पीएम नरेन्द्र मोदी की बढ़ती सक्रियता के क्या हैं मायने?

राजस्थान में करीब सात माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पिछले सात माह से पीएम मोदी ने अपने तूफानी दौरे से प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटें साध ली हैं। राजस्थान के लोगों में पीएम मोदी की दीवानगी ऐसी है कि कई सभाओं में जब सीएम गहलोत भाषण देने के लिए माइक संभालते हैं तो जनता की ओर से मोदी-मोदी के नारे गुंजायमान होने लगते हैं।

बीजेपी ने पीएम मोदी को राजस्थान चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा बनाते हुए पिछले आठ महीनों में उनके जरिए प्रदेश की 200 में से 109 विधानसभाओं के मतदाताओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खुद के साथ जोड़ने का सफल प्रयास किया है। इन 109 में से 41 सीटें भाजपा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीती थीं। यानी इनमें आधी से ज्यादा वो सीटें हैं, जो अभी दूसरे दलों या निर्दलीयों के खाते में हैं। बीजेपी की रणनीति इन्हीं सीटों पर सैंध लगाने और खुद के गढ़ को और मजबूत करने की है। गहलोत वर्सेज पायलट के चलते जहां कांग्रेस की सभाओं में गुटबाजी नजर आती है, वहीं बीजेपी की सभाओं में कार्यकर्ता एकजुटता के साथ उत्साहित नजर आ रहे हैं।

पीएम ने पिछले दौरे में मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर, राजसमंद और गोडवाड़ के जालोर, पाली एवं सिरोही तक के लोगों से सभा के जरिए सीधे संवाद किया। इन पांच जिलों की 27 विधानसभा सीटों में से 19 भाजपा के खाते में हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सिरोही, आबूरोड पर उसी जगह जनसभा को संबोधित किया जहां वे 30 सितंबर 2022 को आए थे और मोदी करीब 8 महीने पहले आबू रोड आए थे, लेकिन रात 10 बजे के बाद माइक पर बोलने की अनुमति नहीं होने के कारण उन्होंने भाषण नहीं दिया था। तब उन्होंने वादा किया था कि वे यहां फिर जरूर आएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए पीएम मोदी फिर आबू रोड पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनता-जनार्दन से किए हुए वादे को भला मैं कैसे भूल सकता था? जब मैं नवरात्र के दौरान आया था तो आपसे कोई बातचीत नहीं कर पाया था। कानून की मयार्दाएं थीं और अनुशासन में रहना मेरा स्वभाव और संस्कार है। उस दिन आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। बहुत रात होने के बावजूद आप मुझे आशीर्वाद देने आए थे। मुझे लग रहा था कि आपको नाराज करके जा रहा हूं, पता नहीं कितना गुस्सा निकलेगा। लेकिन राजस्थान के लोगों का दिल बड़ा है। आप लोग आज भी कितनी बड़ी संख्या में भरपूर आशीर्वाद देने आए हैं।

राजस्थान में पीएम मोदी के दौरे के दौरान की सात बड़ी बातें

1- कल यानी 13 मई को जयपुर बम धमाकों के 15 साल पूरे होंगे। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी वही किया, जिसके लिए वह कुख्यात रही है। आतंकियों पर हमेशा नरम रुख अपनाया है। उसका इतिहास-कारनामे ऐसे ही कुख्यात रहे हैं। बम धमाकों के केस में कमजोर पैरवी की, आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है। तुष्टिकरण की नीति का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा?

2- कांग्रेस ने वोट की राजनीति के लिए सूडान में फंसे लोगों को चेहरा जगजाहिर कर दिया, उनकी जान खतरे में डाल दी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सूडान में एक को भी गोली लग गई तो उन्हें कर्नाटक में चुनाव में खेल खेलने का मौका मिल जाएगा।

3- पिछले 5 साल में राजस्थान में राजनीति का एक भद्दा रूप देखा है। यहां कुर्सी लूटने, कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। यह कैसी सरकार है कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है ! यह कैसी सरकार है कि विधायकों को सीएम पर भरोसा नहीं है !! यह कैसी सरकार है, जिस पर उसके खुद के दिल्ली-दरबार को भरोसा नहीं है !!! सब एक-दूसरे को अपमानित करने की होड़ में लगे हैं। ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी।

4- राजस्थान की जनता में पीएम मोदी के प्रति दीवानगी का यह आलम था कि गहलोत भाषण देने के लिए माइक पर आए तो पंडाल से मोदी- मोदी का नारा लगने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से ही लोगों को शांत रहने की अपील की, लेकिन फिर भी दर्शक मोदी- मोदी के नारे लगाते रहे। ऐसा नहीं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने मोदी- मोदी की नारेबाजी पहली बार हुई है। सीएम गहलोत को इससे पहले भी कई बार मोदी- मोदी के नारों का सामना करना पड़ा है। पोकरण के बाबा रामदेव के मंदिर में दर्शन के दौरान और जयपुर में सीएम गहलोत आईपीएल मैच देखने पहुंचे उस दौरान भी स्टेडियम में मोदी मोदी नारों से सामना करना पड़ा था।

5- कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून-व्यवस्था तबाह हो चुकी है। हालात यह हैं कि बहन-बेटियों की आबरू राजपूतों की इस धरती पर खतरे में है। राजस्थान देश भर में दुष्कर्म के मामलों में शर्मनाक तरीके से नंबर वन पर है। जिस राजस्थान में अपराध सुनने में कम आते थे, वहां अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। वोट बैंक की गुलामी में चल रही कांग्रेस लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसकी सबसे बड़ी कीमत माताओं, बहनों और बेटियों को चुकानी पड़ी है। उन्हें तीज-त्योहार भी शंका-आशंका के बीच मनाने पड़ते हैं।

6 - जब देश में कोरोना महामारी आई तो कांग्रेस ने अफवाह फैलाई, कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो। मोदी इन लोगों की धमकियां और साजिशों के आगे न झुका है, न झुकेगा। यदि मोदी झुकता है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता है। आप ही मेरे मालिक हैं।

7- इस पूरी राजनीति में एक बात समझ आई कि कांग्रेस अभी भी मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था कि मोदी हैड्डसंकट में फंसे हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार सकते हैं। मोदी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती।

सीटों का गणित : पीएम मोदी ने सात माह में ऐसे नापा आधा राजस्थान

1 नवंबर 2022: भाजपा ने पीएम की इस सभा के जरिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कनेक्ट किया था। इसके जरिए इन 2 जिलों की 9 विधानसभा सीटों को साधा गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों जिलों में भाजपा को 3 सीटें मिली थीं।

28 जनवरी 23: गुर्जरों के आराध्य भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा की थी। इसके जरिए पीएम ने अजमेर और भीलवाड़ा जिलों को साधा था। अजमेर की 8 विधानसभाओं में भाजपा के पास 5 सीटें हैं, जबकि भीलवाड़ा की सात विधानसभाओं में से भाजपा के पास चार सीटें हैं।

12 फरवरी 23: पीएम का दौसा दौरे के दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले हिस्से का उद्घाटन करके पूर्वी राजस्थान को साधा। इसमें दौसा, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर तक शामिल था। पीएम ने जयपुर वैशाली नगर स्टेडियम में सभा को संबोधित किया था। ऐसा करके इन आठ जिलों की 58 सीटों को साधा। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों में से भाजपा के खाते में 11 गई थी।

खरी बात

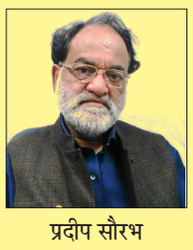

प्रदीप सौरभ
पत्रकार व उपन्यासकार

पूरी ताकत झौंककर भी कर्नाटक क्यों हार गई भाजपा

कर्नाटक के बाद इस साल अब पांच अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है। इसके अलावा अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद सात राज्यों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर अगले दो सालों में लोकसभा के साथ-साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। इनमें कई दक्षिण के राज्य भी हैं। इसलिए भाजपा के लिए कर्नाटक की हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, मुश्किलों में घिरी कांग्रेस के लिए जीवनदान साबित हुई।

लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कर्नाटक में भाजपा क्यों हार गई? वो कौन से कारण थे, जिसके चलते भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा? अब भाजपा आगे क्या करेगी?

दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर्नाटक चुनाव में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही थी और कांग्रेस काफी आक्रामक थी। लेकिन कुछ ऐसे कारण जिससे भाजपा की हार साफ दिख रही थी जिसे ज्यादातर एक्जिट पोल ने भी दिखाया।

आंतरिक कलह बनी मुसीबत: ये सबसे बड़ा कारण है। चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि इससे काफी पहले से भाजपा में आंतरिक कलह की खबरें सामने आ चुकी थीं। कर्नाटक भाजपा में कई धड़े बन चुके थे। एक मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीएस येदियुरप्पा का गुट था, दूसरा मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का, तीसरा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और चौथा भाजपा प्रदेश नलिन कुमार कटील का था। एक पांचवा फ्रंट भी था, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का था। इन सभी फ्रंट में भाजपा के कार्यकर्ता पिस रहे थे। सभी के अंदर पॉवर गेम की लड़ाई चल रही थी।

टिकट बंटवारे ने बिगाड़ा बाकी खेल : पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही थी। ऐसे समय में टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी हुई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं का अलग होना भी पार्टी के लिए नुकसान साबित हुआ।

भ्रष्टाचार के आरोपों ने पहुंचाया नुकसान : ये मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहा। चुनाव से कुछ समय पहले ही भाजपा के एक विधायक के बेटे को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इसके चलते भाजपा विधायक को भी जेल जाना पड़ा। एक ठेकेदार ने भाजपा सरकार पर 40 प्रतिशत कमिशनखोरी का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में जोरशोर से उठाया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी तक ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। जनता के बीच भाजपा की छवि धुमिल हुई और पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।

दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई का भी असर : इसे भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं। इस वक्त दक्षिण बनाम उत्तर की बड़ी लड़ाई चल रही है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और मौजूदा समय केंद्र की सत्ता में है। ऐसे में भाजपा नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ की लड़ाई में मौन रखना ठीक समझा। वहीं, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मुखर होकर इस मुद्दे को कर्नाटक में उठाया। नंदिनी दूध का मसला इसका उदाहरण है। कांग्रेस ने नंदिनी दूध के मुद्दे को खूब प्रचारित किया। एक तरह से ये साबित करने की कोशिश की है कि भाजपा उत्तर भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि दक्षिण के लोगों को किनारे लगाया जा रहा है।

आरक्षण का मुद्दा पड़ा भारी : ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का एलान कर दिया। इसने भाजपा के हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। लिंगायत वोटर्स से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया।

विशेष खबर हिन्दी साप्ताहिक

REGISTERED & ADMINISTRATIVE OFFICE:
ए-288 नेहरू नगर द्वितीय, गाजियाबाद, उ0प्र0
(Mob.) 9711345310

संपादकः विनीतकांत पाराशर
समाचार संपादक : सुनील कुमार वर्मा
ले-आउट डिजाइनः रजनी वर्मा

समाचार, लेख व विज्ञापन के लिए संपर्क करें
e-mail: visheshkhabarvk@gmail.com,
visheshkhabar.tv@gmail.com
contact: (Mob.) 9711345310

@ विशेष खबर में छपे सभी लेख व खबरों पर हुए वाद विवाद को सुलझाने के लिए न्याय क्षेत्र गाजियाबाद में मान्य होगा।

GHAZIABAD POLICE COMMISIONRATE OFFICER IMPORTANT CONTACT NUMBER

Commissioner office		0120–2820758
Commissioner	- Ajay Mishra	9643322900
ADCP	- P.Dinesh Kumar	9643320500
DCP-City	- Nipun Agarwal	9643322901
DCP-Rural	- Ravi Kumar	9643322902
DCP-Trans Hindon	- Vivek Chandra Yadav	9643322903
ADCP-Crime	- Gyanendra singh	9643322905
DCP-Traffice	- Rama Kuswaha	9643322897
ADCP	- Protocal-S.Gangwar	9643322890
ACP-Office	- Avnish Kumar	9643320207
ACP Kotwali	- Anshoo Jain	9643322906
ACP Nandgram	- Alok Dubay	9643322907
ACP Indrapuram	- Swatntra Singh	9643322908
ACP Sahibabad	- Poonam Mishra	9643322909
ACP Loni	- Rajnees Upadhyay	9643322910
ACP Masoori	- Nimishh Dashrath	9643322911
ACP Crime/Traffice	- Bhaskar Verma	9643320599
ACP Kavinager & A/C	- Abhishek Srivastav	9643208958
ACP Wave City	- Ravi Prakash Singh	9643320404
ACP Modi Nager	- Ritesh Tripathi	9643322912
RI Insp Line	- Udal Singh	9643322890

महापुरूषों के विचार

स्वामी विवेकानंद

'जैसा तुम सोचोगे, वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे।'

virul tweet fact chek of the week

फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर बीबीसी न्यूज का एक कथित ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में 'द केरल स्टोरी' के समर्थन की बात कही गई है। ट्वीट को असली समझकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे वायरल कर रहे हैं। इसकी जांच की गई तो यह पूरी तरह फर्जी साबित हुआ। बीबीसी असली ट्वीट के साथ छेड़छाड़ करके वायरल ट्वीट तैयार किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैंसले पर उद्धव-फडनवीस में जुबानी जंग

वार

उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं है। इस सरकार में नैतिकता नहीं है। अगर इस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस में जरा भी नैतिकता है तो जैसे मैंने इस्तीफा दिया था, इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जवाब में फडनवीस ने ठाकरे पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे को शोभा नहीं देता। मैं उनसे पूछता हूं कि भाजपा के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री बनने के लिए जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए तब नैतिकता को कौन से डब्बे में डाला था ? उन्होंने डर के कारण इस्तीफा दिया था।

पलटवार

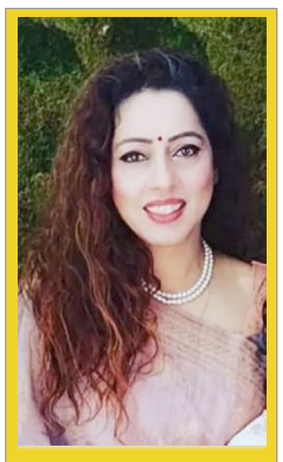

डॉ. नीति एस शर्मा
ज्योतिष,वास्तु व रत्न विशेषज्ञ
राजनीतिक विश्लेषक

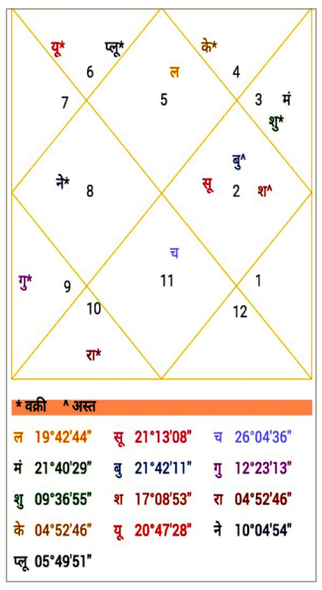

* वक्री	^ अस्त				
ल	19°42'44"	सू	21°13'08"	च	26°04'36"
मं	21°40'29"	बु	21°42'11"	गु	12°23'13"
शु	09°36'55"	श	17°08'53"	रा	04°52'46"
के	04°52'46"	यू	20°47'28"	ने	10°04'54"
प्लू	05°49'51"				

ज्योतिष फैक्टर

एक बार फिर सच साबित हुई डॉ. नीति एस शर्मा की भविष्यवाणी

यूपी और कर्नाटक चुनावों के नतीजों पर डॉ. नीति शर्मा ने पहले ही कर दी थी सटीक भविष्यवाणी

ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद डॉ. नीति एस शर्मा ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि यूपी चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजय मिलेगी। साथ ही दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से खोई हुई कांग्रेस की पहचान उन्हें वापिस मिलेगी। डॉ. नीति एस शर्मा ने कहा कि योगी जी की कुंडली में बहुसंख्य राजयोग बनते हैं। जिसमें लग्नेश सूर्य का अपने सवोच्च दिशा बल के स्थान दशम भाव में लाभेष और धनेष बुध के साथ युति होना, पंचमेश गुरू का पंचम भाव में होकर लग्न और भाग्य स्थान पर दृष्टि देना, योगकारक व भाग्य के स्वामी मंगल का दशम भाव के स्वामी शुक्र के साथ लाभ भाव में युति करना अथवा राहु का छठे भाव में होकर शत्रुहनता योग का निर्माण करना और केतु का बारहवें भाव में स्थित होकर धर्म का ध्वज लहराना, जैसे प्रमुख ज्योतिषीय योग बनते हैं ।

योगी जी की जन्म तारीख 5 अंक के स्वामी बुध भी उनकी कुंडली में अमात्य कारक बनके, उनको बुद्धि और वाणी की कुशलता प्रदान करते हैं। योगी जी वर्तमान समय में केतु में बुध की अंतरदशा अथवा बुध में शुक्र की प्रत्यन्तर दशा से गुजर रहे हैं। जिसके प्रभाव से उनको यूपी में नारी शक्ति का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा। महिला वोटर्स बढ़-चढ़कर यूपी में कमल के पक्ष में वोट डालेंगी। जिसके फलस्वरूप डॉ. नीति एस शर्मा के कथन के अनुसार उनकी एक-एक भविष्यवाणी सच साबित हुई है।

वहीं उन्होंने दिसंबर 2022 में इस बात की भी भविष्यवाणी की थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की वापिसी में विशेष योगदान देगी। राहुल गांधी जी की कुंडली में, वे मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। मंगल उनकी कुंडली में छठे भाव में विराजकर , उनके साहस में वृद्धि करते हैं और उनको लड़ने का कौशल प्रदान कर रहे हैं। उनकी कुंडली में शुक्र और शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी कहीं न कहीं उनको जनता के करीब लेकर आया हैं। जिसकी वजह से उनको कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल हुई हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के निकाय चुनाव और कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। जिनमें निकाय चुनाव यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत हरसिल हुई है तो कर्नाटक में कांग्रेस की बडी जीत से उसकी सरकार बन रही है।

ज्ञान सरोवर

जो मित्र का दुख बिना कहे समझे, वही सच्चा मित्र-संत राम प्रसाद

मित्र के कहे बिना जो मित्र के चेहरे का भाव पढकर मित्र के दुःख को या परेशानी को जान ले एवं उसकी मदद करे, वही सच्चा मित्र है जैसे तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्ण ने गरीब ब्राह्मण मित्र सुदामा को बिना जताए, बिना बताए उनकी मदद की क्योंकि वो जानते थे कि गरीब सुदामा संकोच एवं स्वाभिमान के कारण कुछ नहीं मांगेंगे। पूछने पर उनके सम्मान को ठेस भी लगेगी परंतु उनके पैरों के छालों को देखकर भगवान ने मित्र की आर्थिक स्थिति का आंकलन कर लिया और रातों रात सुदामा की गरीब कुटिया को महल में परिवर्तित कर दिया।

उक्त विचार रामद्वारा लक्ष्मीगंज में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत रामप्रसाद ने कथा के अंतिम दिन व्यक्त किए। कृष्ण-सुदामा प्रसंग को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि संकट एवं जरूरत के समय मित्र को अहसान जताए बिना, मित्र के स्वाभिमान की रक्षा के साथ की गई मदद सच्ची मित्रता की पहचान है। कृष्ण एवं सुदामा की दोस्ती मित्रता का आदर्श उदाहरण है जो ये संदेश देता है कि मित्रता अमीरी-गरीबी का भेद नहीं करती। बुरे समय में साथ रहे दोस्तों को अच्छा समय आने पर नजरंदाज नहीं करना चाहिए। मित्र द्वारा लाई गई भेंट को उसके मूल्य के आधार पर आंकलन न करके उसमें छिपे प्रेम को देखना चाहिए। जैसे भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा द्वारा लाये गए तीन मु-ठठी चावलों के स्वाद में 56 भोग से भी ज्यादा आनंद पाया और तीन मुठ्ठी चावल के बदले सुदामा की दरिद्रता दूर कर दी। जैसे स्वयं द्वारिकाधीश तीनों लोकों के स्वामी जिस सुदामा के मित्र हों वो गरीब हो ही नहीं सकता, वैसे ही श्रीकृष्ण जैसा सच्चा मित्र होने पर कोई दुःखी नहीं हो सकता है।

आनंदित रहने के लिए है जिंदगी

संतजी ने सुदामा चरित्र के पश्चात भगवान कृष्ण के गोलोकधाम पधारने की लीला को कहा एवं नव योगेश्वर की कथा को विस्तार से बताया। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु के माध्यम से बताया कि जिसको शिक्षा लेनी है वह कहीं से भी शिक्षा ले सकता है और जिसको शिक्षा नहीं लेनी है वह सत्संग में आकर के भी अधूरा रह जाता है। 24 गुरुओं के माध्यम से बताया कि जिंदगी आनंदित रहने के लिए है, उदास रहने के लिए नहीं है। निराश रहने के लिए नहीं है। जीवन उसी का खुशहाल होता है जिसने गुरुओं के ज्ञान को जीवन में उतारा है।

काव्य रचना

तीन पहर तो बीत गये,
बस एक पहर ही बाकी है।
जीवन हाथों से फिसल गया,
बस खाली मुट्ठी बाकी है।

सब कुछ पाया इस जीवन में,
फिर भी इच्छाएं बाकी हैं
दुनिया से हमने क्या पाया,
लेखा - जोखा बहुत हुआ,
इस जग ने हमसे क्या पाया,
बस ये गणनाएं बाकी हैं।

इस भाग-दौड़ की दुनिया में
हमको इक पल का होश नहीं,
वैसे तो जीवन सुखमय है,
फिर भी क्यों संतोष नहीं !
क्या यूं ही जीवन बीतेगा,
क्या यूं ही सांसें बंद होंगी ?
औरों की पीड़ा देख समझ
कब अपनी आंखें नम होंगी ?
मन के अंतर में कहीं छिपे
इस प्रश्न का उत्तर बाकी है।

मेरी खुशियां, मेरे सपने
मेरे बच्चे, मेरे अपने
यह करते - करते शाम हुई
इससे पहले तम छा जाए
इससे पहले कि शाम ढले
कुछ दूर परायी बस्ती में
इक दीप जलाना बाकी है।
तीन पहर तो बीत गये,
बस एक पहर ही बाकी है।
जीवन हाथों से फिसल गया,
बस खाली मुट्ठी बाकी है।

पुस्तक समीक्षा

बेगम हजरत महल यानि 'परीखाने' की महकपरी

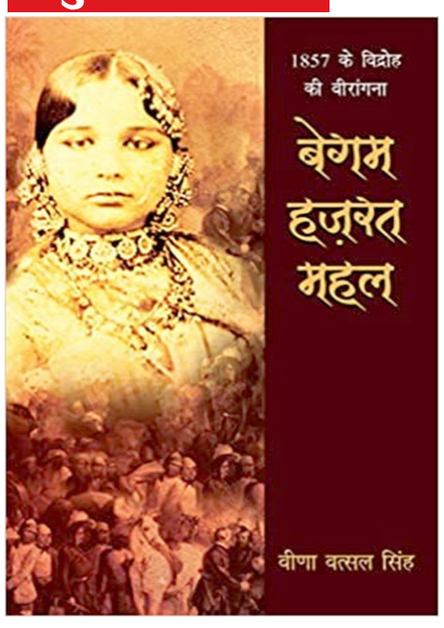

इन दिनों ऐतिहासिक उपन्यासों का दौर है। ऐसे में अवध के नवाब वाजिद अली शाह की छोटी बेगम के रूप में मशहूर बेगम हजरत महल के बारे में पढ़ना सुखद लगता है, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था।

लेखिका ने उपलब्ध इतिहास से लेखकीय छूट ली। लेकिन उनकी पूरी कोशिश रही कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को वैसा ही रखें। उन्होंने बेगम हजरत महल के पूरे जीवन को उपन्यास में समेटा है। वे स्वाभिमानी, साहसी और प्रेमिल थीं। जिनकी वीर गाथा उनके व्यक्तित्व और संघर्षों की संपूर्णता है।

साधारण परिवार में जन्मी और पली-बढ़ी लेकिन बचपन से ही जुझारू और साहसिक व्यक्तित्व की स्वामिनी बालिका 'मोहम्मदी' को गहने-कपड़े नहीं बल्कि तलवारबाजी का शौक है। यही बालिका परिस्थिति वश नवाब वाजिद अली शाह के 'परीखाने' पहुंच जाती है और उसे नाम मिलता है, महक परी। महक की सादगी, सच्चाई और साहस उन्हें महल की अन्य परियों से अलग खड़ा करते हैं। यही महक एक दिन अपनी वीरता और विलक्षणता के दम पर नवाब का दिल जीतकर उनकी मलिका बेगम हजरत महल बन जाती है।

शुरूआती महिला क्रांतिकारियों में से एक बेगम हजरत महल की हैरतगेज दास्तान रोचक भाषा शैली और प्रवाहमय शिल्प में रची गई है। 1857 की क्रांति के समय के अवध के सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन पर गहन शोध के बाद लिखे गए इस श्रमसाध्य उपन्यास में नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल की लोक प्रचलित छवियों को लेकर भी कई मिथक टूटने का अहसास होता है। विशेषकर वाजिद अली शाह जो रंगीले नाम से विख्यात थे। यकीनन यह किताब स्थायी मुकाम बनाने के सारे कारण प्रस्तुत करती है।

बेगम हजरत महल
वीणा वत्सल सिंह
राजपाल एंड सन्स
मूल्यः 325 रु.
पृष्ठः190

असल सच

लिंडा को ट्विटर में लाकर खुद ये काम करेंगे मस्क

एनबीसी यूनिवर्सल में ग्लोबल एडवरटाइजिंग एंड पार्टनरशिप की पूर्व अध्यक्ष लिंडा याकारिनो की ट्विटर के सीईओ के रूप में नियुक्ति से एलन मस्क को टेस्ला पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल जाएगा। मस्क की भूमिका अब कार्यकारी अध्यक्ष और प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम ऑपरेशन्स की देखरेख करने वाले सीटीओ के रूप में बदल जाएगी। मस्क ने कहा लिंडा को लाने से मुझे टेस्ला को अधिक समय देने का मौक मिल रहा है जो कि मैं कर रहा हूं। टेस्ला की ऑपरेटिंग इनकम 2023 की पहली तिमाही में 24 फीसदी घटकर 27 बिलियन डॉलर हो गई क्योंकि मस्क द्वारा संचालित ईवी निमार्ता अपने वाहनों की कीमतों में कटौती जारी रखे हुए है। मस्क ने कहा कि टेस्ला 2023 की तीसरी तिमाही में लंबे समय से विलंबित साइबरट्रक की डिलीवरी शुरू कर देगी

विशेष खबर में अपने लेख पुस्तक समीक्षा, गीत, कविता, साक्षात्कार, ज्योतिषीय आंकलन आदि प्रकाशित कराने के लिए रचनाएं हमारे ईमेल पते पर भेंजे। visheshkhabar.tv@gmail.com

मनोरंजक खबर- बॉलीवुड- टेलीविजन

बॉयकाट के दौर में क्या खत्म हो जाएगा बॉलीवुड

या कंट्रोवर्सी से पैसा कमाएंगी फिल्में

आज कल फिल्में न तो गानों की वजह से मशहूर हो रही हैं। न ही एक्टर-एक्ट्रेस की वजह से। आज कल बॉयकट बॉलीवुड चला है जहां लोग साउथ की फिल्मों को देखना और उनके गाने सुनना पसद कर रहे हैं। इतना ही नहीं आज कल तो एक्टर एक्ट्रेस भी बॉलीवुड छोड़ आपना साउथ की फिल्मों में हाथ साफ कर रहे हैं। कहने को तो बॉलीवुड में कई सितारे हैं जो अपनी खुद की मेहनत से नाम कमा रहे हैं। पर कहते हैं न एक सड़ा सेब सारे अच्छे फलो को भी खरब कर देता है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड में हो रहा है जहां कुछ नेपोकिड्स की वजह से पूरे बॉलीवुड का नाम खराब हो रहा है। यह नेपोटिज्म या बॉयकॉट बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हो रहा है। जहा छिछोरे मूवी के बाद ऐसी कोई भी मूवी नहीं आई जो बिना कंट्रोवर्सी से हिट हुई हो। जहां लोग अक्षय कुमार को देखने के लिए पागल होते थे। वहीं अब अक्षय कुमार की बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप होते हुए नजर आ रही हैं। चाहे वो लक्ष्मी मूवी हो या फिर कठपुतली।

आमिर खान 4 साल में एक ब्लॉकबस्टर मूवीज लाने के लिए फेमस हैं वहीं उनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा ने सिनेमा घरो में आपना जादू नहीं चलाया। अब यह बॉयकॉट बॉलीवुड का ही कमाल है जहां अलिया भट्ट RRR मूवी में काम करने गई। हाल की ही बात कर लेते हैं जहां पठान मूवी में इतने बड़े सितारे थे पर बॉयकॉट का डर उन्हें भी सताने लगा जहां उन्होंने बिकनी के रंग की कंट्रोवर्सी कर दी। जबकि इससे पहले भी तमाम फिल्मों में भगवा रंग की बिकनी और कपड़े पहने गये हैं।

पर तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मूवी आई लोगों में इतना क्रेज हो गया था कि कंट्रोवर्सी है क्यों? यह पता लगने के लिए लोगों ने मूवी को ब्लॉकबस्टर मूवी बना दिया और शारुख खान के फैंस और दीपिका के फैंस ने उन्हें नाराज नहीं किया। कंट्रोवर्सी को गलत साबित करने में लोग मूवी के कंटेंट को देखना ही भूल गये। कई लोगों ने कहा भी कि SRK सलमान भाई की कॉपी कर रहे हैं।

अब जो भी मूवी आ रही हैं वो बस कंट्रोवर्सी का सहारा लेके आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में आई THE KERALA STORY की ही बात कर लें तो लोगों ने Kshmir Files की ही तरह इसे भी ब्लॉक बस्टर हिट करवा दिया। हालांकि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ का कहना है कि फिल्म प्रोपोगेंडा बेस्ड है। तो कुछ कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आई है।

मूवी की रेटिंग काफी अच्छी है और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में हाउसफुल भी रही है। पर अलग अलग जगहों से अलग अलग रिएक्शन भी हैं। जैसे बंगाल में मूवी को बैन कर दिया गया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री मूवी की कास्ट से मिल रहे हैं। चाहे जो भी रिएक्शन मिला हो सच्चाई यह है कि मूवी ने कमाई खूब की है। कुछ दिनों पहले रिलीज होने वाली मूवी 'सिर्फ एक बंदा काफी है' इसका बस ट्रेलर आते ही यह मूवी विवादों में आ चुकी है।

यह मूवी मनोज बाजपाई की है और इस मूवी के लिए उन्हें आसाराम बापू ने लीगल नोटिस तक भेज दिया है। अब यह मूवी भी कंट्रोवर्सी का फायदा लेकर आगे बढ़ेगी जैसे अब तक होता आ रहा है या फिर यह ट्रेंड यही खत्म हो जायेगा।

बिग बजट फिल्मों पर

नवाजुद्दीन सिद्दकी ने ठीक ही कहा है

बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार खराब प्रदर्शन कर रही हैं। केवल इस साल रिलीज हुई आधा दर्जन से अधिक फिल्में या तो फ्लॉप रही हैं या फिर डिजास्टर साबित हुई हैं। इनमें कार्तिक आर्यन की फिल्म 'शहजादा' (बजट- 75 करोड़ और कलेक्शन 47 करोड़), अक्षय कुमार की फिल्म 'सेल्फी' (बजट- 110 करोड़ और कलेक्शन 23 करोड़), रणबीर कपूर की फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' (बजट- 110 करोड़ और कलेक्शन 100 करोड़) और अजय देवगन की फिल्म 'भोला' (बजट- 100 करोड़ और कलेक्शन 79 करोड़) का नाम शामिल है। ये सभी फिल्में बॉलीवुड के बड़े सुपर सितारों की हैं, जिनकी एक वक्त बॉक्स ऑफिस पर तूती बोलती थी। लेकिन आज सुपर फ्लॉप हैं। बिग बजट फिल्मों के लेकर बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि ऐसी फिल्में ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने काम कर रही हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मई में 'अफवाह' और 'जोगीरा सारा रा रा' दो फिल्में रिलीज होने जा रही हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि बिग बजट फिल्मों में न तो कोई कहानी होती है, न ही एक्टिंग और न ही डायरेक्शन। ऐसी फिल्में बड़े सितारों को लेकर फॉमूर्ला बेस्ड बनाई जाती हैं। इसकी वजह है कि दर्शक ऐसी फिल्मों को लगातार खारिज कर रहे हैं। जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बुरे दौर की तरफ ले जा रही है।

नवाजुद्दीन का कहना है, 'बिग बजट फिल्मों में कोई कहानी नहीं होती है। इनमें कुछ गाने ले लिए जाते हैं, जिन्हें कोरियोग्राफर डिजाइन करते हैं। कई फिल्मों में एक्शन होता है, तो उसे एक्शन डिजाइनर तैयार कर देते हैं। इसमें डायरेक्टर या एक्टर क्या करता है, ये समझ से परे है। इसके साथ ही फिल्म मेकर्स कुछ खास एक्टर्स को लेकर फिल्में बनाते हैं, जिन्हें लोग देखना भी नहीं चाहते। एक जनता का एक्टर होता है और दूसरा इंडस्ट्री का। दूसरे वाले वापस आते रहते हैं, लेकिन दर्शक उन्हें पसंद नहीं करते हैं।' नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मानना है कि बड़े बजट की ज्यादातर फिल्में इन्हीं वजहों से फ्लॉप हो रही हैं। देखा जाए तो नवाज की बातों में दम है।

सार समाचार

सुप्रीम फैंसले के बाद दिल्ली में रूके प्रोजेक्टस को मिलेगी रॉकेट की रफ्तार

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली । नई दिल्ली : दिल्ली में सर्विसेज पर अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली में 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से काम होंगे। उनके इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम में तेजी आएगी। खासकर जिन योजनाओं पर एलजी ने रोक लगा दी थी या फंड की मंजूरी मिलने में हो रही दिक्कतों के चलते जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, ऐसी योजनाओं को सरकार फिर से आगे बढ़ा सकती है। दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में गर्वनिंग बॉडी के गठन को लेकर भी लंबे समय से सरकार और एलजी के बीच विवाद चल रहा है। अब सरकार इस दिशा में भी तेजी से एक्शन लेते हुए गर्वनिंग बॉडीज का गठन कर सकती है। इसके अलावा बिजली कंपनियों के बोर्ड में भी सरकार एक बार फिर से अपनी पसंद के लोगों को नॉमिनेट करके उन्हें बोर्ड का सदस्य बना सकती है। पिछले साल एलजी ने सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए लोगों को हटाकर उनकी जगह सरकारी अफसरों को बोर्ड का सदस्य बना दिया था।

पिछले साल एलजी की तरफ से लगाई गई आपत्तियों के बाद अफसरों ने दिल्ली सरकार द्वारा लगाई जाने वाली फ्री योग क्लासेज के लिए फंड जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब सर्विसेज पर कंट्रोल मिलने के बाद सीएम फ्री योग क्लासेज को फिर शुरू करवा सकते हैं।

मोहल्ला क्लिनिकों का विस्तार

दिल्ली में 521 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। इनमें 5 महिला मोहल्ला क्लिनिक्स भी शामिल हैं। मोहल्ला क्लिनिकों के विस्तार की योजना के तहत इनकी संख्या को बढ़ाकर 1000 करना था, लेकिन अफसरों और एलजी के साथ शुरू हुए विवाद के चलते इस योजना पर काम आगे नहीं बढ़ सका। अब दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों के विस्तार के काम को तेजी से आगे बढ़ा सकती है।

बाजारों का री-डिवेपलमेंट

पिछले साल बजट में दिल्ली सरकार ने राजधानी के 5 प्रमुख बाजारों को री-डिवेलप करने का ऐलान किया था। साथ ही दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करने और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने की घोषणा भी की थी। जी-20 के मद्देनजर दिल्ली के कुछ अन्य प्रमुख बाजारों को भी संवारने का प्लान था, लेकिन पहले एमसीडी से सहयोग न मिलने और उसके बाद अधिकारियों द्वारा कई स्तरों लगाई गई अड़चनों और फंड्स न मिलने के चलते इनमें से किसी भी योजना पर काम शुरू नहीं हो सकता। शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन भी टालना पड़ा। अब सरकार इस योजना को भी फिर से आगे बढ़ा सकती है।

दिल्ली सरकार की कई प्रमुख योजनाओं की प्लानिंग करने, रिसर्च और डेटा कलेक्शन करने, सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने और जनता को होने वाले फायदे को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का खाका तैयार करने वाले दिल्ली सरकार के थिंक टैंक दिल्ली डायलॉग एंड डिवेलपमेंट कमीशन का कामकाज भी अब फिर से पटरी पर लौट सकता है। एलजी ने कमीशन के वाइस चेयरमैन जास्मिन शाह की नियुक्ति, उन्हें मिली सुविधाओं और उनकी शक्तियों पर कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद शाह के दफ्तर को सील करके उनकी सुविधाएं वापस लेने का आदेश जारी किया गया था। शाह ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती भी दे रखी है। सर्विसेज पर सरकार को अधिकार मिलने के बाद सीएम अब डीडीसी की भी बहाली का आदेश जारी कर सकते हैं।

एक्साइज पॉलिसी पर भी नजर

पिछली बार नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार को काफी चुनौतियों का सामना पड़ा। विवाद के चलते अभी तो पुरानी पॉलिसी को ही फिर से लागू कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार नई पॉलिसी लाने के लिए प्रयासरत है। सर्विसेज पर कंट्रोल आने के बाद दिल्ली सरकार एक बार फिर नई एक्साइज पॉलिसी लाने का प्रयास कर सकती है।

लाडली योजना के 364 करोड़ बैंक में क्या कर रहे हैं? जवाब दो केजरीवाल

दिल्ली सरकार में एक ओर घोटाले की आहट

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति और 'ऑपेरशन शीशमहल' में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और मामले में केजरीवाल सरकार घिर सकती है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से लाडली योजना से जुड़ी एक जनहित याचिका पर उसका रुख जानना चाहा है। इसमें योजना को उसके असल मकसद को पूरा करने के लिए इसे ढंग से लागू करने की मांग की गई है। इस योजना का उद्देश्य बच्चियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करके उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच के सामने दायर याचिका में दावा किया गया है कि योजना के तहत उपलब्ध 364 करोड़ रुपये की राशि का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। आकाश गोयल नाम के शख्स ने अपनी याचिका में कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, लाडली योजना की 21 साल से अधिक उम्र की 1,82,894 लाभार्थियों की 364 करोड़ रुपये से अधिक राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास पड़ी है और यह राशि सही तरीके से वितरित की जानी चाहिए। एडवोकेट विभोर गर्ग और केशव तिवारी के जरिए दायर याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2008 को 'दिल्ली लाडली योजना' शुरू की थी।

इसके तहत लाभार्थी की उम्र 18 साल होने पर उसके खाते में एक लाख रुपये सरकार द्वारा जमा कराए जाते हैं। याचिका में दावा किया गया कि योजना के तहत उपलब्ध धनराशि का सही तरीके से वितरण नहीं किया जा रहा है। मामले में अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

हिंडन नदी में नहाने आए कोंडली के दो भाईयों की डूबने से मौत एक लापता

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। गाजियाबाद में हिंडन नहर में रविवार शाम नहाने आए दिल्ली-कोंडली के पांच बच्चों में से तीन गहरे पानी में डूब गए। दो बच्चों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अग्निशमन टीम की मदद से दो बच्चों के शव बाहर निकाले। तीसरे की तलाश में पांच घंटे से ज्यादा समय तक ऑपरेशन चला। जबकि दो का सकुशल बचा लिया गया। खोड़ा पुलिस ने हादसे की सूचना गाजीपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली कोंडली में रहने वाले पांच बच्चे किसी काम से घर से निकले थे। सभी घूमते हुए हिंडन नहर के किनारे पहुंचे गए। पांचों नहर में नहाने के लिए अंदर कूद गए। गहरे पानी में पहुंचने पर दो सगे भाई वीर (17 वर्ष) और धर्म (14 वर्ष) पुत्र लेखराज व तरुण (14 वर्ष) पुत्र राजवीर डूबने लगे। उन्हें देखकर दोनों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी डूबने लगे। तब दोनों किसी तरह नहर से बाहर निकले और तुरंत पुलिस को हादसे की सूचना दी।

खोड़ा थाना प्रभारी योगेंद्र मलिक मौके पर पहुंचे और तुरंत एनडीआरएफ व अग्निशमन टीम को ऑपरेशन के लिए बुलाया। इस बीच निजी गोताखोर तीनों की तलाश में नहर में कूद पड़े। काफी देर प्रयास के बावजूद तीनों का कुछ पता नहीं चला। एनडीआरएफ और अग्निशमन टीम ने पानी में मशीन डालकर नीचे के प्रेशर को ऊपर उठाया तो धर्म और तरुण ऊपर आ गए। टीम ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। टीम ने वीर की तलाश में भी ऑपरेशन चलाया, लेकिन पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद उसे ढूंढने में सफलता नहीं मिली। पुलिस ने हादसे की सूचना गाजीपुर थाना पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस ने भी परिजनों का पता करके उन्हें हादसे के बारे में बताया। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि दो बच्चों को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तीसरे की तलाश भी कर रहे हैं। परिवार को हादसे की सूचना दे दी है।

दिल्ली में सरकार व एलजी के अधिकारों की लडाई में अफसरों को सता रहा डर

पॉवर गेम की लड़ाई फिर अदालती चक्रव्यूह में फंसी

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला देते हुए ये तय कर दिया कि दिल्ली में सर्वेसर्वा चुनी हुई सरकार ही है। इस फैसले के आने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में जश्न का माहौल है, लेकिन इसी बीच नौकरशाही अमले में खलबली सी मची हुई है। पूरे नौकरशाही तंत्र इस फैसले के बाद चिंता में है और ये सोच-सोच कर उनकी पेशानी पर बल पड़ रहे हैं कि फैसले की प्रतिक्रिया का उन पर क्या असर होगा?

लेकिन ये फैंसला आए एक दिन भी नहीं बीता होगा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसकी ओर से जारी ट्रांसफर ऑर्डर पर अमल की कार्यवाही नहीं कर रही। दरअसन अदालत का आदेश आने के बाद सर्विसेज विभाग के सेक्रटरी आशीष माधवराव मोरे का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह को पोस्टिंग दी। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र ने इस आदेश पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल ही आपने आदेश दिया था और अब 141 के तहत अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह मामला सुनने के लिए बेंच का गठन करेंगे।

फैसला आने के 6 घंटे के अंदर ही हो गया था पहला तबादला

'सर्विसेज' पर अधिकार मिलते ही दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 6 घंटे के अंदर ही दिल्ली सरकार ने तबादले का पहला आदेश जारी कर दिया। पहली गाज भी सर्विसेज विभाग के सेक्रेट्री पर ही गिरी। शाम को दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विभाग के सचिव आशीष माधवराव मोरे के तबादले का आदेश जारी कर दिया। उनकी जगह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह को सर्विसेज विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ए.के. सिंह दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं।

दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि तबादले के लिए अधिकारियों की एक लंबी लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से फाइनैंस,

पीडब्ल्यूडी, लेबर, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, होम, विजिलेंस जैसे कई अन्य प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

अधिकांश अधिकारियों को सता रहा है डर

शीर्ष नौकरशाही सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अधिकांश अधिकारी बहुत खुश नहीं हैं। उनका डर है कि उन्हें अब कई तरह के नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कई सालों से एलजी सचिवालय और दिल्ली की एनसीटी की चुनी हुई सरकार के बीच लड़ाई चल रही थी। अब इस फैसले से खींचतान और तेज होगी और नौकरशाहों को लग रहा है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।

चुनी हुई सरकार के आदेश मानने होंगे

शीर्ष नौकरशाही के सूत्रों ने बताया कि फैसले के तुरंत बाद, उनके वाट्सएप ग्रुप में इस तरह के मैसेज सकुर्लेट हो रहे हैं, साथ ही अलग-अलग परिणामों की कल्पना की जा रही है। कई नौकरशाहों का ऐसा मानना है कि इस आदेश के बाद एक बार जब गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के साथ किसी नौकरशाह को नियुक्त कर देगा तो उन्हें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के आदेशों का ही पालन करना होगा। उन्हें अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा रखा जाएगा।

अफसरों को सता रहा कार्रवाई का डर

सूत्रों के मुताबिक, उनके और मौजूदा सरकार के साथ पहले के अनुभव बहुत सुखद नहीं रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार, अपने साथ काम करने वाले किसी भी अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय को लेना है क्योंकि केंद्र सरकार अभी भी इस उद्देश्य के लिए कैडर-नियंत्रक प्राधिकरण है।

भर्ती करने की अंतिम शक्ति केंद्र के पास

एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों में भी तैनात किया जा रहा है और इन राज्यों की सरकारों को उनके अधीन तैनात अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति है। इसके बाद मामला केंद्र सरकार को भेजा जाता है। कुछ अफसरों का विचार है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा कुछ स्पष्टता दिए जाने तक दिल्ली सरकार द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैबिनेट को सेवाएं देने के बावजूद भर्ती करने की अंतिम शक्ति केंद्र के पास है।

'केंद्र के पास दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एजीएमयूटी कैडर है। ग्रे क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली इस आदेश के बाद अपने स्वयं के लोक सेवा आयोग की मांग करे, जिसने अंततः उन्हें सेवाओं पर नियंत्रण दिया था? यदि वे ऐसी मांग उठाते हैं तो दिल्ली में राज्यपाल का क्षेत्र नहीं है, जो कि सिफारिश करेंगे,'

नौकरशाहों में है भ्रम का जाल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उनका भविष्य कैसा होगा, इसे लेकर नौकरशाहों के अंदर एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है। कई अधिकारी पूछ रहे हैं कि गृह मंत्रालय की वास्तविक भूमिका क्या होगी? अब तक, उनके स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए हस्ताक्षर करने का अधिकार एलजी के पास था और अब वही भूमिका दिल्ली के सीएम द्वारा निभाई जाएगी, जब तक कि वह किसी अन्य मंत्री को यह अथॉरिटी नहीं सौंपते। यहां तक कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा अन्य मामलों से संबंधित सभी फाइलें दिल्ली एलजी को नहीं भेजी जाएंगी। अब तक किसी भी विभाग से संबंधित सभी फाइलों को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के सचिवालय में भेजा जाता था। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट नई याचिका पर कब सुनवाई करेगा।

नई नवेली दुल्हन ने ध्वस्त किया आजम का रामपुर किला

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

रामपुर। यूपी नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गया। निकाय परिणाम कई जिलों में चौंकाने वाले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर नगरपालिका परिषद का रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही रहा है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सना खानम ने रामपुर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के पद पर जीत दर्ज कर एक अलग ही माहौल बना दिया है। हालांकि, इस जीत में सना खानम के पति ममून शाह की भूमिका बड़ी है।

ममून शाह ने करीब तीन दशक तक कांग्रेस के लिए काम किया। ममून शाह ने नगरपालिका अध्यक्ष की लगातार दावेदारी की, लेकिन इस बार ममून को बड़ा झटका तब लगा, जब निकाय आरक्षण सूची जारी की गई। सूची में रामपुर नगरपालिका सीट को महिला के लिए आरक्षित किया। ममून शाह की उम्र 45 वर्ष हो गई थी, लेकिन अविवाहित थे। आरक्षण सूची जारी होने के बाद ममून ने अचानक शादी करने का फैसला किया। 15 अप्रैल को 36 वर्ष की सना खानम से उन्होंने शादी की। 17 अप्रैल तक निकाय चुनाव का नामांकन होना था।

ममून शाह कहते हैं कि हमने अपने सपने को पूरा करने के लिए इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। हमने शादी करने का फैसला ले लिया।

यह सब काफी तेज घटा है।

उन्होंने शादी के बाद कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयास किया, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद पत्नी सना खानम के साथ आप में शामिल हो गए। पार्टी का टिकट लिया और जीत हासिल कर ली।

मामून शाह की बेगम सना खानम ने 43,115 वोट हासिल कर रामपुर नगरपालिका अध्यक्ष बन गई। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 10,958 वोटों के अंतर से हराया।

नामांकन समाप्त होने के दो दिन पहले तक शायद सना खानम ने भी नहीं सोचा होगा कि वह रामपुर नगरपालिका के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने वाली हैं। हालांकि, अब वह पालिकाध्यक्ष बन चुकी हैं।

इस चुनाव में मामून शाह का यह निकाह वाला प्रयोग खासी चर्चा में रहा। ममून कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारी उपेक्षा की। लोगों के बीच ह-मने काम किया था। अब शहरवासियों को एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

सना खानम कहती हैं कि पति के शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के सपने को पूरा कराएंगे। साथ ही, उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के शहरों को लेकर किए गए कार्य को भी रामपुर में पूरा कराने की बात कही।

रामपुर नगरपालिका परिषद सीट पर पिछले दो दशक से समाजवादी पार्टी का कब्जा था। सना खानम कहती हैं कि हमें क्षेत्र के लोगों ने शादी का उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि जब ममून शाह ने हमारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने तुरंत हां कर दी। सना रामपुर से पीजी तक की पढ़ाई की हैं।

स्वार टांडा और छानबे विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा के सहयोगी दल ने मारी बाजी

स्वार-टांडा विधानसभा सीट पर मिट्टी में मिला सपा का वर्चस्व

▶ प्रदेश की जनता को योगी सरकार के विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत कानून व्यवस्था पर विश्वास है

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

लखनऊ। सबका साथ, सबका विकास, सबका वि-श्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रही योगी सरकार का यूपी में जनाधार और मजबूत होता जा रहा है। इसकी झलक उत्तर प्रदेश में दो विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भी देखने को मिली, जहां भाजपा समर्पित अपना दल (एस) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करायी। रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट पर भाजपा समर्पित अपना दल (एस) के उम्मीदवार

शफीक अहमद अंसारी ने 27 साल के सपा के वर्चस्व को मिट्टी में मिलाकर आजम खां के किले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उधर, छानबे विधानसभा सीट पर भी भाजपा समर्पित अपना दल (एस) की उम्मीदवार रिंकी कोल ने जीत दर्ज कराई है।

योगी सरकार विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत कानून व्यवस्था से प्रदेशवासियों के दिलों पर कर रही राज:

प्रदेश की जनता को योगी सरकार के विकास का विजन काफी भा रहा है। वहीं प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि योगी सरकार का उपचुनाव के साथ नगर निकाय के चुनाव में भी प्रदेश की जनता का पूरा साथ मिला है। प्रदेश में गरीबों को फ्री में आवास, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं कोरोना काल खंड से लेकर अब तक 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 500000 प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर और नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। 2017 से पहले माफिया नौजवानों को बहलाकर उनके हाथों में तमंचे थमा दिया जाता था। योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत हो रही कार-वाई काफी रास आ रही है।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। योगी सरकार नौजवानों के टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें नया आयाम दे रही है, जिससे योगी आदित्यनाथ हर वर्ग के पसंदीदा मुख्यमंत्री बन गये हैं।

स्वार टांडा में विजेता शफीक को मिले 68630 वोट:

स्वार टांडा में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल (एस) को विजय मिली। अपना दल के शफीक अहमद अंसारी ने 68630 वोट हासिल किए। वहीं सपा उम्मीदवार अनुराधा चौहान को 59906 वोट मिले। पीस पार्टी की उम्मीदवार डॉ. नाजिया सिद्दीकी को मजह 4688 वोट से संतोष करना पड़ा। भाजपा सहयोगी दल के उम्मीदवार को कुल 50.81 वोट फीसदी वोट मिले, जबकि सपा के खाते में 44.35 फीसदी वोट ही आए। भाजपा के सहयोगी दल के शफीक अंसारी ने 8724 वोट से सपा की अनुराधा चौहान को मात दी है। 1996 में विधानसभा चुनाव के बाद से स्वार विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी और आजम खान के कब्जे में थी। 2023 में हुए उपचुनाव में भाजपा अपना दल के प्रत्याशी ने स्वार विधानसभा सीट से आजम खान और समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ कर दिया हैं।

नए सीबीआई डाइरेक्टर प्रवीण सूद की कांग्रेस से अदावत क्या गुल खिलाएगी

धर्मेन्द्र पांडे @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। अगले दो साल कांग्रेस के लिए फिर से मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्योंकि कर्नाटक के डीजीपी और 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद अगले दो साल के लिए सीबीआई के डाइरेक्टर बन गए हैं। इसे संयोग कहें या सियासी रणनीति कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की सत्ता जाने और कांग्रेस के सत्ता में आने के कुछ घंटो बाद ही प्रवीण सूद को सीबीआई निदेशक बनाने का ऐलान कर दिया गया। इससे कयास लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस की राह आसान नहीं होंने वाली है, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता डी के शिवकुमार से उनकी जबरदस्ती तल्खी रही है।

बताया जा रहा है कि प्रवीण सूद के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहमत थे। लेकिन सूद के नाम पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को जबरदस्त ऐतराज रहा। हांलाकि माना जा रहा है कि प्रस्तावित

सूची में सूद ही सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। इसी आधार पर पीएम और सीजेआई ने उन्हें देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सौंपने का मन बनाया। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली तीन सदस्यीय समिति में पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। शनिवार को दिल्ली में हाई-पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई थी।

सूत्रों का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने बड़े विस्तार से सूद की उम्मीदवारी के खिलाफ दलीलें रखीं थी। उनका ऐतराज इस बात पर था कि सूद आईपीएस अधिकारियों के उस पूल का हिस्सा नहीं थे जो केंद्र में डीजीपी लेवल पर सेवा के योग्य हों। फिर भी पीएम और सीजेआई की राय एक होने से सूद की दावेदारी मजबूत हो गई। रविवार दोपहर उनकी नियुक्ति का ऐलान कर दिया गया।

सीबीआई की कमान अभी सुबोध कुमार जायसवाल के हाथ में है जिनका दो साल का कार्यकाल सोमवार को खत्म हो रहा है, तभी सूद कार्यभार संभाल सकते हैं। हालांकि सूद के रिटायरमेंट की तारीख 31 मई, 2024 है। लेकिन उन्हें सीबीआई डायरेक्टर बनाने के बाद उनका कार्यकाल मई 2025 तक दो साल के लिए फिक्स किया गया है।

जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवीण सूद के अलावा 1986 बैच के अधिकारियों में सीआईएसएफ प्रमुख शीलवर्धन सिंह, जो अगस्त में रिटायर हो रहे हैं तथा एनएसजी प्रमुख एम. ए गणपति जिन्हें मार्च 2024 में रिटायर होना उनके नाम सीबीआई डाइरेक्टर के लिए भेजे थे। गणपति के पास सीबीआई में काम करने का अनुभव है जबकि सूद ने पहले कभी सीबीआई में काम नहीं किया है।

हिमाचल प्रदेश में जन्में और आईआईटी दिल्ली से ग्रेजूएट प्रवीण सूद का ज्यादातर कार्यकाल कर्नाटक पुलिस में रहा है। प्रवीण सूद के प्रति कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की तल्खी जगजाहिर है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सूद को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा था कि वे डीजीपी पद के लायक नहीं है।

प्रवीण सूद ने चुनाव के दौरान करीब 25 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को भी लिखा था। अब राज्य में कांग्रेस सत्ता में आ गई है लेकिन प्रवीण सूद सीबीआई निदेशक के रूप में दिल्ली का रुख करेंगे तो देखना होगा कि कांग्रेस से उनकी दुश्मनी क्या गुल खिलाती है।

सार समाचार

गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में जीते पार्षदों की सूची

वार्ड संख्या	पार्षद का नाम	दल का नाम
1	नीतू नागर	बसपा
2	मंजू	निर्दलीय
3	भगवत स्वरुप	निर्दलीय
4	गोपाल शिशोदिया	बीजेपी
5	पिंकी	बीजेपी
6	सुनैना	बीजेपी
7	मुन्नीदेवी कश्यप	बीजेपी
8	मिथलेश तिटोरिया	बीजेपी
9	शीतल देओल	बीजेपी
10	रेखा गोस्वामी	बीजेपी
11	छाया त्यागी	बीजेपी
12	प्रवीण कुमार उर्फ राहुल	कांग्रेस
13	रजनी	बीजेपी
14	ओमप्रकाश ओड	बीजेपी
15	पूनम सिंह	बीजेपी
16	नीलम जाटव	बीजेपी
17	जयकिशन	बीजेपी
18	शशि सिंह	बसपा
19	उर्मिला चौहान	बीजेपी
20	यशपाल ज्ञानी	भाजपा
21	आनंद गौतम	निर्दलीय
22	विनीत	बीजेपी
23	जगत सिंह	निर्दलीय
24	पवन कुमार गौतम	बीजेपी
25	कन्हैया	बीजेपी
26	राजकुमार राजू	बीजेपी
27	नरेश जाटव	निर्दलीय
28	सुधीर	बीजेपी
29	ओमपाल भाटी	बसपा
30	रीना	बीजेपी
31	नितिनकुमार	निर्दलीय
32	सुभाष सिंह	बसपा
33	धीरेन्द्र यादव	निर्दलीय
34	खुशीर्दा बेगम	समाजवादी पार्टी
35	रीतू चौधरी	निर्दलीय
36	प्रतिभा शर्मा	बीजेपी
37	रवि भाटी	भाजपा
38	मनोज पाल	बीजेपी
39	उदित मोहन	बीजेपी
40	हिमांशु चौधरी	बीजेपी
41	भूपेन्द्र कुमार	भाजपा
42	प्रमोश यादव	निर्दलीय
43	जोगेन्द्र सिंह	निर्दलीय
44	पवित्री देवी	सपा
45	सुनंदा सिंह	बीजेपी
46	अजयवीर सिंह	बीजेपी
47	अमित त्यागी	बीजेपी
48	शाजीदा	समाजवादी पार्टी
49	वीरेंद्र त्यागी	बीजेपी
50	सुनीता पाल	निर्दलीय
51	सीमा यादव	बीजेपी
52	अभिषेक चौधरी	बीजेपी
53	सुमन चौधरी	बीजेपी
54	सतेन्द्र पाल	बीजेपी
55	सन्तोष सिंह	बीजेपी
56	मनोज त्यागी	बीजेपी
57	राधेश्याम त्यागी	बीजेपी
58	देव नारायणशर्मा	बीजेपी
59	राजीवशर्मा	बीजेपी
60	सचिन डागर	बीजेपी
61	शिल्पा चौधरी	बीजेपी
62	मीनू डबास	बीजेपी
63	शहरोज परवीन	आप
64	तबससुम जहान	एआईएमआईएम
65	राजकुमार नागर	बीजेपी
66	मुस्तकीम चौधरी	आप
67	अजय शर्मा	कांग्रेस
68	विनय चौधरी	बीजेपी
69	कुलदीप त्यागी	बीजेपी
70	राम निवास	बीजेपी
71	उमेश नागर	बीजेपी
72	मनोज गोयल	निर्दलीय
75	हिमांशु शर्मा	निर्दलीय
76	गौरव सौलंकी	बीजेपी
77	नीलम भारद्वाज	बीजेपी
78	ओमवती	बीजेपी
79	हरीश	बीजेपी
80	राहुल शर्मा	बीजेपी
81	धीरज अग्रवाल	बीजेपी
82	किरनदेवी	सपा
83	कविता	बीजेपी
84	परवीन चौधरी	बीजेपी
85	प्रमोद	बीजेपी
86	मदन	बीजेपी
87	अनुज त्यागी	निर्दलीय
88	नीरज गोयल	बीजेपी
89	राजकुमार	बीजेपी
90	आदिल मलिक	सपा
91	शीतल शर्मा	बीजेपी
92	रुबीना	एआईएमआईएम
93	सिमरन मलिक	सपा
94	कृष्ण मोहन	निर्दलीय
95	रुख्साना सैफी	आप
96	अजीत निगम	निर्दलीय
97	श्रीकान्त अग्रवाल	बीजेपी
98	अनिल तोमर	बीजेपी
99	प्रीति जैन	बीजेपी
100	अजय सिंह	बीजेपी

गाजियाबाद में बद से बदतर होती कांग्रेस को बडी सर्जरी की जरूरत

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। एक तरफ तो कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है वहीं दूसरी ओर सबसे बड़े सूबे में उसके प्रदर्शन ने पार्टी की गंभीरता की पोल खोल दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भले ही कांग्रेस ने सत्ता में वापसी ली हो परंतु उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन दयनीय ही रहा है। केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ऐसे में नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन से इसके समर्थकों को निराशा ही हाथ लगी है। अगले साल ही देश में आम चुनाव भी होने हैं।

गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में तो आलम यह रहा कि कुल सौ वार्डों में से तीस पर तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार तक भी नहीं उतार पाई। लोकसभा चुनाव के लिए अब साल भर से भी कम समय बचा है और इनमें सफलता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को एक लंबी दूरी तय करनी होगी।

नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को

गाजियाबाद में हुए पिछले कई चुनावों के मुकाबले इस बार सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। जहाँ पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा लगभग सवा लाख वोट लेकर दूसरे स्थान पर रही थीं वहीं इस बार उसकी प्रत्याशी पुष्पा रावत करीब साठ हजार वोट ही प्राप्त कर सकीं और बसपा उम्मीदवार के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। नगर निगम के वार्डों में तो कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो गया और सदन में इसके पार्षदों की संख्या 15 से घटकर 3 रह गई है।

कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी मेयर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी तो लोग इसे कांग्रेस का एक बड़ा दाव मान कर चल रहे थे। इसकी एक खास वजह भी थी। दरअसल पुष्पा रावत उत्तराखण्ड मूल से आती हैं और गाजियाबाद में वहाँ के मतदाताओं की एक अच्छी-खासी संख्या निवास करती है।

माना जा रहा था कि पुष्पा रावत उत्तराखण्ड मूल के यदि आधे मतदाताओं का रुख भी अपनी ओर मोड़ने में कामयाब हो गई तो गाजियाबाद के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ी पुष्पा रावत इसमें पिछड़ती ही चली गई। पुष्पा रावत उत्तराखण्ड के मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ना तो दूर उनके बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में भी नाकामयाब ही साबित हुई।

कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने पुष्पा रावत के चुनाव प्रचार से शुरू से ही खासी दूरी बनाए रखी। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र

भारद्वाज तो स्वास्थ्य कारणों से पार्टी प्रत्याशी के प्रचार से दूर रहे लेकिन, नगर निकाय चुनाव में इसके लगभग अन्य सभी कद्दावर नेताओं की उदासीनता समझ से परे है। कुछ लोग कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को इसकी बड़ी वजह बता रहे हैं। खैर, वजह चाहे कोई भी बताई जा रही हो कांग्रेस की इस हार के लिए वर्तमान महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी की भी अहम जिम्मेदारी बनती है।

अपनी पार्टी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में वो कांग्रेस के सभी धड़ों को एक साथ लाने में पूरी तरह विफल साबित हुए जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अपनी आधी-अधूरी तैयारी और कद्दावर नेताओं की चुनाव प्रचार से दूरी गाजियाबाद के इतिहास में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार की गवाह बनी। पुष्पा रावत महज 58,951 वोट ही प्राप्त कर सकीं और बसपा की निसारा खान सेभी पिछड़कर तीसरे स्थान पर सिमट गई। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अगर कांग्रेस को अपना पुराना आधार और प्रतिष्ठा वापस चाहिए तो उसे मामूली मरहम पट्टी नहीं बल्कि बडी सर्जरी करनी होगी तभी वह सत्ता में वापसी के ख्वाब देखे। दिलचस्प बात ये हैं कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पुष्पा रावत शहर की कद्दावर महिला नेता डॉली शर्मा के भरोसे चुनाव प्रचार करती नजर आई। हैरानी तो इस बात की हैं कि उत्तराखंड के बड़े कांग्रेसी नेता हरीश रावत जो उनकी ही बिरादरी के हैं वे भी उनके समर्थन में सभा या रोड शो करने नहीं पहुंचे।

जिले में बसपा–सपा की जगह केजरीवाल और औवेसी बन रहे मुस्लिमों की पसंद

जिले में निकाय चुनाव के परिणामों से निकला संदेश

सुनील वर्मा @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। मुस्लिम बहुल वार्डों में इस बार झाड़ू और पतंग ने जगह बना ली है। इन इलाकों के मतदाताओं ने बसपा, साइकिल और पंजे को निराश किया है। मतदाता कई दलों में बंटे नजर आए। 100 में से तीन में आम आदमी पार्टी और दो वार्डों में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल पार्टी के प्रत्याशी ने पार्षद का चुनाव जीत लिया है।

प्रेम नगर कैला भट्ठा वार्ड की बात करें तो यहां आठ बूथ हैं। पिछली बार यहां से कांग्रेस के टिकट पर जाकिर सैफी पार्षद बने थे। इस बाद वार्ड का आरक्षण बदलने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर वार्ड 92 से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। वार्ड 95 से उनके भाई की पत्नी रुकसाना सैफी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ीं और जीत गईं। उन्हें 2021 वोट मिले। इस सीट पर पिछले चुनावों में बसपा, कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने पुराने दलों को नकार कर नए दलों को मौका दिया है।

वार्ड 92 से एआईएमआईएम की रूबीना को 1795 मत मिले जबकि सपा की शबनम को 988 वोट ही मिल सके। बूथ नंबर 1182 पर एआईएमआईएम को 135 वोट मिले जबकि भाजपा को इस बूथ पर मात्र तीन वोट मिले हैं। इस बूथ पर 2017 में सबसे अधिक वोट कांग्रेस को मिले थे। वहीं वार्ड नंबर 95 प्रेमनगर कैला में झाड़ू ने सभी दलों को पीछे छोड़ दिया। यहां दूसरे नंबर पर बसपा रही। सपा तीसरे और चौथे पर कांग्रेस रही। कैला प्रेमनगर वार्ड की आबादी करीब 18000 है। रुकसाना सैफी ने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की नुसरत जहां को हराया। रुकसाना को 2021 और नुसरत को 1118 वोट मिले।

वार्ड 66 में आप ने चौधरी मुस्तकीम को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के आसिम को हरा दिया। मुस्तकीम को 1537 वोट मिले

जबकि आसिम को 1501 वोट मिले। यहां भी बसपा और सपा के वोटरों का ध्रुवीकरण हो गया। बसपा की आपसी खींचतान का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। मुस्लिम मतदाता बंट गए। यहां करीब 10 हजार मतदाता हैं। इस वार्ड से 2107 में सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी।

वार्ड 63 पसौंडा से आप प्रत्याशी शहरोज परवीन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी की परवीन को हरा दिया। शहरोज को 1447 और परवीन को 978 वोट मिले। यहां भी मुस्लिम मतदाता आप का साथ हो लिए। सपा और कांग्रेस हाशिए पर रही। इन सीटों पर पहली बार इन दलों का खाता खुला है। 2017 में शहरोज इसी वार्ड से सपा से पार्षद चुनी गई थीं।

वार्ड नंबर 64 गरिमा गार्डन से एआईएमआईएम की तबस्सुम ने बीजेपी की रूबी डागर को हरा दिया। यह वार्ड भाजपा के पास था। 2017 में तेजपाल राणा भाजपा से पार्षद थे। इस बार भाजपा ने रूबी को उम्मीदवार बनाया था। तबस्सुम को 4207 वोट मिले हैं जबकि रूबी को 2237 वोट मिले हैं।

हाजी जमीर बेग का कहना है कि मुस्लिम समाज में बहुत जागरूकता आ गई है। उन्हें कोई बहका नहीं सकता है। अपने बीच के उम्मीदवारों को चुना गया है।

आई जी एफ - राष्ट्रीय खेल 2023

नोएडा इंडोर स्टेडियम में शानदार आगाज के बाद खिलाडियों को खेल अलंकरण से हुआ समापन

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। इंटरनेशनल गेम्स फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड द्वारा नोएडा इंडोर स्टेडियम नोएडा में आयोजित आई जी एफ राष्ट्रीय खेलो 17 राज्यो की टीमो ने भाग लिया उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश,पंजाब, वेस्ट बेंगाल, महाराष्ट्र, आदि थे। खेलों का शुभारभ उत्तर प्रदेश के कबीना मंत्री जसवंत सैनी, नोएडा के भाजपा सांसद महेश शर्मा, प्यारेलाल जाटव, विनोद डूंगर राजदूत मलावी, नीरज गुप्ता, नवीन पाराशर, रामू गुप्ता (ब्राउन बेकरी) जीशान जैदी, कर्नल संदीप मित्तल आदि ने किया। मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियो के लिये हर सुविधा मुहैया कराएगी। समापन समारोह नरेन्द्र कश्यप (मंत्री पिछड़ा वर्ग उत्थान) ने किया और पुरुष्कार दिए।

आयोजन अध्यक्ष अनिल कौशिक ने बताया इस अवसर पर मंत्री जसवंत सैनी ने अलग खेलों के लिये राष्ट्रीय खेल अलंकरण सम्मान वितरित किये।

क्रॉसबो में अतिशय कौशिक , राम सिसोदिया, मौसमी साहू, राज कुमार, प्रधुम्न सिंह को दिया। डार्ट शूटिग में कनिका सिसोदिया, शूटिंग में राजू केसावन , राज कुमार चौहान, तमिलनाडु तथा राहुल शर्मा उत्तराखंड, सौरभ सहारनपुर को दिया। टाईक्वांडो में दशरथ सिंह शेखावत, अब्दुल समाद, मिक्स्ड नेट बाल में नरेंद्र शर्मा, कबड्डी में बीएसएफ के आनंद, जुडो में दिल्ली पुलिस के प्रवीण भारद्वाज, कराते में रजनीश चौधरी, अमित गुप्ता, सचिन त्यागी, अमर चौहान, दिनेश, पवन वर्मा, दिलीप कश्यप, अलका, आशीष, अब्दुल करीम, तरुण शर्मा, संदीप श्रीवास्तव, जम्मू के दिलीप, राजस्थान के विकास शर्मा, मध्य प्रदेश के जसप्रीत सिंह, निर्मल गोस्वामी, सुरजीत छारी, रिया सिंह, राजीव मुंडेलवाल, आसाम के संजीव, त्रिपुरा के सौरव देव, पश्चिम बेंगाल के राकेश शर्मा, राजेश कौशिक, आदि को दिया। कराते में लगभग 500 खिलाड़ियो ने भाग लिया मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय गान के साथ सबका दिल मोह लिया, मंच का संचालन अंश अनिल कौशिक ने किया।

पुरुस्कार वितरण में सनी कश्यप, दीपशिखा कश्यप, सारिका शुक्ला भी शामिल थे। ओवरआल ट्रॉफी उत्तर प्रदेश से अमित गुप्ता के नेतृत्व की टीम ने जीती जबकि रनर अप टीम आसाम की रही।

जीडीए में ऑनलाइन नक्शा पास कराना होगा ओर आसान

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। शहर में ऑनलाइन नक्शा पास कराना अब काफी आसान हो जाएगा। जल्द ही यहां गाजियाबाद डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑनलाइन नक्शा पास करने के सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे लोगों को लेटलतीफी और अन्य परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता हटते ही इस नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा।

पब्लिक को भी मिल जाएगी राहत

अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में जब सॉफ्टवेयर में नक्शा अपलोड किया जाएगा तो उसमें एनओसी और अन्य तरह के कागजात को आवेदक को लगाना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो स्क्रूटनी के दौरान ही वह रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वह पहले

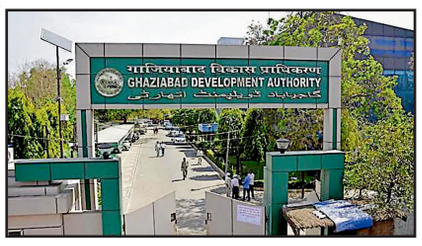

से इस स्तर की पूरी तैयारी करके ही नक्शे को पोर्टल पर डालेगा तो उसकी समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जीडीए के चक्कर लगाने से वह बच जाएगा।

अभी लंबे समय तक फंसे रहते हैं नक्शे

जीडीए के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष में जीडीए के ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर 1798 नक्शे पास करने के आवेदन आए। इसमें से 47 नक्शे को निरस्त कर दिया गया। जबकि 641 नक्शे किसी न किसी कारण से पेंडिंग चल रहे थे। जबकि अन आवासीय के 400 नक्शों के आवेदन आए। इसमें 99 को निरस्त किया गया। 223 आवेदन लंबित चल रहे थे। ग्रुप हाउसिंग के नक्शे की बात करें तो 46 नक्शे जमा हुए। इसमें से 12 को निरस्त कर दिया गया। जबकि 29 आवेदन लंबित चल रहे थे।

क्या बोले अधिकारी

मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के स्तर पर जल्द ही इसका प्रजेंटेशन किया जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही इसे लांच किया जाएगा।

धर्मान्तरण में पादरी गिरफ्तार

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के खोड़ा क्षेत्र में एक महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में एक पादरी और उसकी पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मधु विहार कॉलोनी में रहने वालीं भाजपा कार्यकर्ता सुनीता अरोड़ा की शिकायत पर शनिवार को पुलिस ने पादरी इब्राहिम थॉमस, उनकी पत्नी रीवा और ब्यूटी पार्लर संचालक बबिता को गिरफ्तार किया। सुनीता ने खोड़ा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी बबिता ने उन्हें केरल के मूल निवासी इब्राहिम थॉमस से मिलवाया था जो वर्तमान में कलवरी चर्च में पादरी है। थॉमस अपनी पत्नी रीवा की मदद से धर्मांतरण के लिए हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक सत्रों का आयोजन करते हैं। उन्हें अधिनियम 2021 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

लोनी, खोडा, मुरादनगर में लगा भाजपा विधायकों की साख पर बट्टा

धर्मेन्द्र पांडे @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। एक तरफ पूरे सूबे में योगी मैजिक चल रहा है। योगी का बुलडोजर विपक्षी दलों पर कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी तीन नगर पालिकाओं में हार जाती है। असल में यह हार प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की जरूर है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका जिम्मेदार गाजियाबाद के तीन भाजपा विधायक को माना जा रहा हैं, जिन्होंने हारे हुए उम्मीदवारों का प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर टिकट वितरण में अपनी मनमानी की।

क्षेत्रीय संगठन और पैनल में शामिल पदाधिकारियों को भलीभांति मालूम था कि लोनी-खोड़ा और मुरादनगर में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है उन्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। टिकट सिर्फ उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि माननीय विधायकों का दबाव था तो चलिए शुरूआत खोड़ा कॉलोनी से करते हैं। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और लोकल सांसद के अलावा क्षेत्रीय संगठन ने 3 नामों का पैनल बनाया था जो जीतने की स्थिति में थी। सूत्रों के मुताबिक रीना भाटी का नाम चौथे नंबर पर था लेकिन प्रभारी मंत्री के अलावा सभी लोगों ने यही रिपोर्ट दी थी कि अगर रीना भाटी को यहां चुनाव लड़ाया गया तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है।

इसका मुख्य कारण यह था एक तो रीना भाटी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप नगरपालिका पर लगे। दूसरा कारण अधिकारियों से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज थी। तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य था कि यह सीट जनरल महिला के लिए रखी गई थी तो ऐसे में ओबीसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया गया तो दूसरी जाति के लोगों में असंतोष बढ़ सकता है। लेकिन साहिबाबाद विधायक ने रीना भाटी के टिकट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस सीट को हारने का एक कारण ये भी रहा कि जनरल यहां अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिलाना चाहते थे लिहाजा जब उनकी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला तो उन्हें भी विधायक जी के उम्मीदवार को उसके हाल पर छोड दिया। लिहाजा यूपी में भाजपा की लहर के चलते भी खोड़ा नगर पालिका चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी मोहनी शर्मा पत्नी अमरपाल शर्मा चुनाव जीत गई।

लगभग यही हाल लोनी नगर पालिका का रहा। विधायक नंदकिशोर गुर्जर के दबाव में जिसका टिकट होना था वह नहीं हुआ और जिस का टिकट फाइनल हुआ उसे लोगों ने मन से चुनाव नहीं लड़ाया। नतीजा लोनी नगर पालिका से आरएलडी के सूखे पंप से भी पानी निकलने लगा यानी कि रंजीता धामा चुनाव जीत गईं।

मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजीत पाल त्यागी ने भी यहां अपनी चलाई जिसकी वजह से भाजपा से कई लोग बागी हो गए। हालांकि दबाव में बागियों ने भाजपा का समर्थन कर दिया बाद में लेकिन मन से उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया और भाजपा की सबसे मजबूत सीट कही जाने वाली नगर पालिका आज उसके हाथ में नहीं है। यहां से बसपा की छम्मी चौधरी चुनाव जीत गईं। भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में बड़ी जीत दर्ज कर भाजपा ने कर्नाटक के गहरे घाव को भरने का काम किया है लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तीन नगरपालिका हार कर भाजपा की जीत का मजा संगठन और सरकार के लिए वाकई खराब हो गया, इसको लेकर मंथन बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में तीनों पंचायतों में हुई हार कहीं न कहीं तीनों विधायकों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकती हैं।

नारद मुनि की नगर परिक्रमा

दलित बस्तियों में दौड़ा बसपा का हाथी

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। सपा-रालोद-आजाद समाज पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार सिकंदर पूनम यादव को दलित मतदाताओं का साथ उनकी उम्मीद के अनुरूप नहीं मिल सका। दलित बस्तियों में हाथी की मस्त चाल रही जिसने सिकंदर पूनम यादव के अरमानों पर पूरी तरह से पानी ही फेर दिया।

बसपा प्रत्याशी निसारा खान 63,249 मतों के साथ दूसरे जबकि कांग्रेस की पुष्पा रावत 58,951 मतों के साथ तीसरे और सपारालोद प्रत्याशी सिकंदर पूनम यादव 57,608 मत लेकर चौथे स्थान पर रही।

भाजपा की सुनीता दयाल को सबसे ज्यादा 3,50905 मत प्राप्त हुए। पूनम यादव और उनके पति सिकंदर यादव पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। चुनाव से ऐन पहले ही दोनों पति-पत्नि ने सपा

का दामन थाम लिया था और सपा ने भी पूनम यादव को गाजियाबाद से मेयर का उ-म्मीदवार घोषित कर सभी राजनैतिक पंडितों को चौंका दिया था। सिकंदर पूनम यादव की चुनावी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ से बहुत से लोग सपा के इस कदम को एक मजबूत दाव मानकर चल रहे थे। सकंदर पूनम यादव की सभाओं में बसपा के कोर वोटर माने जाने वाले दलित मतदाता भी काफी बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे थे जिसे देखकर लगने लगा था कि सिकंदर पूनम यादव को दलित वोट भी अच्छी खासी तादात में मिल सकता है। परंतु सिकंदर पूनम यादव चुनावी सभाओं में दिखाई देने वाली दलित मतदाताओं की भारी भीड़ को वोट में तब्दील करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई हैं। आलम यह रहा कि जिस दलित वोट की उम्मीद सिकंदर पूनम यादव के कारण सपा के पाले में जाने की होने लगी थी वह पूरी मजबूती के साथ बसपा के साथ ही डटा रहा।

बसपा उम्मीदवार निसारा खान को मिले 63,249 वोट इसका जीता जागता उदाहरण हैं। सिकंदर पूनम यादव की रणनीति में कहाँ चूक हुई उन्हें नए सिरे से इसका आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। अगले साल होने वाले आम चुनावों का सेमी फाइनल माने जा रहे नगर निकाय के चुनावों में बसपा उम्मीदवारों को मिले वोट यह इशारा करने के लिए काफी हैं कि आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी दिखाई देगी। यह बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए एक शुभ संकेत कहा जा सकता है।

नेता जी चुनाव जूनियर नहीं, सीनियर लीडर ही जिताते हैं ....समझों

भाजपा उम्मीदवार सुनीता दयाल की गाजियाबाद में बडी जीत होगी इसका भी पहले से अनुमान था। वे इतिहास की सबसे बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करेंगी इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कांग्रेस चुनाव में कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी इसमें भी कोई हैरानी जैसी बात नहीं थी। हैरानी हुई तो इस बात पर कि जिनके प्रचार की शुरूआत करने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद गाजियाबाद आए वहीं गठबंधन प्रत्याशी पूनम यादव का मेयर की दौड़ में चौथे नंबर पर रह जाना कई सवालों को जन्म दे गया है।

एक तरफ जहां सुनीता दयाल ने गुटबाजी की तमाम अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा के सभी धड़ों को इस चुनाव में अपने साथ बांधे रखा वहीं सिकंदर पूनम यादव के प्रचार से सपा के तमाम कद्दावर नेताओं ने पूरी तरह से दूरी ही बनाए रखी। पार्टी के मजबूत नेताओं की चुनाव से दूरी भी पूनम यादव के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह रही।

समाजवादी पार्टी ने नामांकन से कुछ समय पहले ही नीलम गर्ग का टिकट काट कर पूनम यादव को अपना मेयर प्रत्याशी बना दिया था। पूनम यादव गाजियाबाद के प्रमुख समाजसेवी और बसपा नेता सिकंदर यादव की हैं। पूनम यादव को सपा से टिकट मिलने के बाद सिकंदर यादव ने बसपा को अलविदा कह दिया था परंतु उन्हें उम्मीद थी कि

बसपा के उनके साथी उन्हें चुनावों में मदद अवश्य करेंगे। हालांकि कुछ जगह सिकंदर यादव को बसपा समर्थकों के वोट भी प्राप्त हुए परंतु अधिकतर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बहुजन समाज पार्टी के कैडर वोट बैंक की उम्मीद और अपने पक्ष में बने जातीय समीकरण ने सिकंदर यादव को अति आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सिकंदर यादव ने सपा के कद्दावर नेताओं की अपने चुनाव से दूरी को कतई भी गंभीरता से नहीं लिया जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा है।

गौरतलब है कि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष साजिद हुसैन, पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद मलिक, पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी, धर्मबीर डबास, जेपी कश्यप और पूर्व विधायक सुरेन्द्र कुमार मुन्नी समेत समाजवादी पार्टी के दर्जनों दिग्गज नेता पूनम यादव के चुनाव प्रचार से पूरी तरह दूरी बनाए रखे।

परंतु भाजपा प्रत्याशी सुनीता दयाल से एकदम उलट सिकंदर यादव ने सपा के इन मजबूत स्तंभों का अपने चुनाव प्रचार में सहयोग लेना भी उचित नहीं समझा। सिकंदर यादव की यह भूल उनके लिए बहुत भारी साबित हुई। पूनम यादव को सुनीता दयाल के मुकाबले में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी समझा जा रहा था परंतु सपा नेताओं की उनके प्रचार से दूरी के चलते वो चौथे स्थान पर खिसक गई। हैरानी की बात ये हैं कि सिंकदर यादव पूरे चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय और यादव बिरादरी से जुड़े छोटे नेताओं को अपने कंधे पर बैठाकर चुनाव प्रचार में जुटे रहे अगर यहीं कवायद उन्होंने बड़े नेताओं को साथ लेकर की होती तो परिणाम बेहतर हो सकते थे। लेकिन नारद मुनि तो शुरू से ही देख रहे थे कि गठबंधन की तरफ अचानक पैराशूट उम्मीदवार उतारे जाने से जिले में पार्टी के दिग्गज नेताओं की भौंहे तनी हुई हैं।

रिकार्ड जीत और विरोधियों की जमानत जब्त कराकर सुनीता दयाल बनीं भगवा गढ़ की प्रथम महिला

निगम में प्रचंड जीत तो पालिका व पंचायतों में हुआ सूपड़ा साफ

▶ प्रदेश में सबसे अधिक मतों से महापौर का चुनाव जीतने वाली सुनीता दयाल ने अपने सभी विरोधियों की जमानत जब्त करा दी।

▶ निगम में पहले से ज्यादा पार्षदों की जीत से साबित हुआ कि शहर में लगातार घट रहा है विपक्ष का जनाधार, भाजपा बढ़ रही हैं।

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। गाजियाबाद को भगवागढ़ ऐसे ही नहीं कहा जाता। नगर निगम निगम चुनाव में महापौर पद पर भाजपा की सुनीता दयाल ने रिकार्ड तोड़ मतों से शानदार जीत दर्ज यूपी में एक ओर रिकार्ड बना लिया है।

शहर की सरकार चुनने के लिए संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में गाजियाबाद से महापौर पद के लिए चुनाव लड़ी भाजपा की सुनीता दयाल ने 2017 की जीत के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। नव निर्वाचित भाजपा मेयर सुनीता दयाल ने प्रचंड जीत के लिए गाजियबाद की जनता का आभार व्यक्त किया है।

भाजपा की सुनीता दयाल को कुल 3,50,905 वोट मिले, उन्होंने 2,87,656 वोटों से महापौर का चुनाव जीतकर बहुजन समाज पार्टी की निसारा खान जो कुल 63,249 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही, 58,951 वोट हासिल कर तीसरे नंबर पर रही काग्रेस प्रत्याशी पुष्पा रावत तथा कुल 57,608 वोट जुटाकर चौथे नंबर पर रही सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी पूनम यादव समेत मेयर पर का चुनाव लड़ने वाले सभी 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा दी।

महापौर पद के लिए भाजपा की सुनीता दयाल समेत कुल 12 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में थीं। भाजपा की महापौर सुनीता दयाल इस ऐतिहासिक जीत से उनका नाम प्रदेश की पहली ऐसी महिला महापौर के रूप दर्ज हो गया है जिसने इतने भारी मतों से जीत दर्ज नहीं कराई है। 11 मई को हुए मतदान में नगर निगम के लिए 39.33 फीसदी वोटिंग हुई थी। नगर निगम के सभी 100 वार्डों के लिए 1275 बूथ पर 2528 ईवीएम मशीन लगाई गई थी।

13 मई शनिवार को नगर निगम महापौर व पार्षदों के अलावा खोड़ा-मकनपुर नगर पालिका परिषद और डासना नगर पचांयत के चेयरमैन व सभासद प्रत्याशियों की भी मतगणना हो गई।

भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल को रिटर्निंग ऑफिसर तथा एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक श्रीवास्तव ने विजयी घोषित किया। काउंटिंग पंडाल में महापौर चुनीं गई सुनीता दयाल को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिहं, पूर्व महापौर आशु वर्मा,पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर,महानगर अध्यक्ष संजीवशर्मा, विजय मोहन, एमएलसी दिनेश गोयल, पार्षद विनय चौधरी आदि की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया। इसके बाद भाजपा कायर्क ताओं व समथर्कों ने सु ीता दयाल के महापौर चुने जाने पर मंडी के गेट के बाहर रोड पर फूल-मालाओं से अभिनंदन किया। महापौर ही नहीं नगर निगम के 100 वार्ड में करीब 66 पार्षद भाजपा के चुनकरआए हैं, जो महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले 2017 में जब अजय शर्मा महानगर के अध्यक्ष थे तब करीब 50 पार्षद जीतकर आए थे।

लोनी में रालोद, खोडा में सपा, मुरादनगर में बसपा को गंवा कर मोदीनगर पंचायत अध्यक्ष ही भाजपा के हाथ लगा

चारों पंचायत अध्यक्ष पद भी भाजपा के हाथ से फिसले

▶ नगर निगम में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भाजपा उप नगरीय क्षेत्र की नगर पालिका व पालिका परिषद की आठ में से सिर्फ एक ही सीट जीत सकी

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। नगर निगम के अलावा जिले में लोनी, खोडा, मुरादनगर, मोदीनगर नगर पालिका परिषद के अलावा नगर पंचायत पतला, निवाड़ी, फरीदनगर व डासना की मतगणना भी संपन्न हो गई हैं।

नगर निगम चुनाव के चुनाव परिणाम जहां भाजपा के लिए उत्साह वर्धक रहे वहीं पालिका व पंचायत के नतीजे भाजपा के लिए काफी चिंताजनक रहे। मोदी नगर को छोड़कर मुरादनगर, खोड़ा व लोनी नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है।

जनपद की चार नगर पालिकाओं में से तीन सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है जबकि इन तीनों सीटों पर टिकटों के बंटवारे में वर्तमान भाजपा विधायकों का दखल साफ तौर पर देखा गया था। इससे इन विधायकों की साख पर भी असर पडेगा।

लोनी नगर पालिका से जहां रालोद प्रत्याशी के रूप मे ंरंजीता धामा ने शानदार जीत दर्ज कराई है वहीं मुरादनगर नगर पालिका सीट पर पूर्व विधायक बहाव चौधरी की धर्मपत्न ी बसपा प्रत्यशी छम्मी चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी रेखा अरोडा को हराकर जीत दर्ज कराई है। यहां भाजपा बागी नेताओं के कारण तीसरे नंबर पर पहुंच गई।

लोनी नगर पालिका में राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी रंजीता धामा ने भाजपा की पुष्पा देवी प्रधान को 18109 वोट से हराया है। इस सीट पर जहां भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पुष्पा देवी के लिए खुलकर प्रचार कर रहे थे, वहीं खतौली से सपा विधायक मदन भैय्या जो लोनी के रहने वाले हैं उन्होंने रंजीता धामा की जीत के लिए कड़ी मेहनत की थी। इस सीट पर दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। वैसे भाजपा की हार में विधायक नंद किशोर गुर्जर के कारण हुई पार्टी की अंदरूनी कलह का भी अहम रोल रहा। विधायक ने पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं का टिकट कटवाने के लिए बगावती तेवर अपना लिए थे जिस कारण उन्हें टिकट ने देकर विधायक की पंसद से पुष्पा देवी को टिकट तो मिल गया लेकिन बताते हें कि नाराज होकर वे अपने घर बैठ गए और सपा जीत गई। हालांकि अगर बसपा, एआईएमएम व कांग्रेस से मुस्लिम उममीदवार मैदान में न होते तो रंजीता धामा की जीत का अंतर शायद ओर बड़ा होता।

खोड़ा नगर पालिका की सीट भी पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा की धर्मपत्नी व सपा प्रत्याशी मोहिनी शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व चेयरमैन रीना भाटी को चुनाव में करारी शिकस्त देकर अपने कब्जे में कर ली है। मोहिनी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और निर्वतमान चेयरमैन रीना भाटी को लगभग 8000 मतों के अंतर से हरा दिया। मोहिनी शर्मा की जीत को साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा के लिए भविष्य की चुनौती माना जा रहा है।

टिकट बंटवारे के बाद बगावत करने वालों को न मना पाने का बड़ा खामियाजा भाजपा को मुरादनगर में भुगतना पड़ा। मुरादनगर नगर पालिका अध्यक्ष की सीट बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक वहाब चौधरी की पत्नी छम्मी चौधरी ने निर्दलीय रेखा अरोड़ा को 1390 वोट से हराकर दिया। यहां भाजपा प्रत्याशी रमा देवी तीसरे स्थान पर रही हैं। भाजपा की कोर वोटर मानी जाने वाली शहरी आबादी ने मुरादनगर में इस बार कमल का साथ नहीं दिया। भाजपा ने इस बार महानगर मंत्री गोपाल अग्रवाल की पत्नी रमा को टिकट दिया था। भाजपा के टिकट पर ही 2012 में चुनाव जीत चुकीं रेखा अरोड़ा के लिए उनके पति राधेश्याम अरोड़ा ने टिकट मांगा था। टिकट ने मिलने पर उन्होंने पत्नी से निर्दलीय नामांकन करा दिया। राधेश्याम लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं। संगठन में भले कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला, लेकिन समाज पर उनकी पकड़ मजबूत है। आम वोटर के साथ व्यापारी वर्ग भी उनकी पत्नी को टिकट न मिलने से खफा था।

केवल मोदीनगर नगर पालिका चेयरमैन पद पर ही एक मात्र भाजपा प्रत्याशी भाजपा को केवल एक मोदीनगर नगर पालिका सीट मिलने पर संतोष करना पड़ेगा। जहां भाजपा के विनोद वैशली ने पहली बार 33000 हजार वोटों के अंतर से नगरपालिका अध्यक्ष की सीट पहली बार जीती गई है। यहां रालोद, बसपा, सपा के कद्दावर प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई।

इसके अलावा फरीदनगर पचायत सीट आजाद समाज पार्टी की रेशमा ने जीतकर जहां पार्टी का खाता खोला तो डासना नगर पंचायत की सीट बसपा की बागे जहां ने, पतला नगर पंचायत चेयरमैन की सीट पर रालोद की रीता और निवाडी नगर पंचायत चेयरमैन सीट सपा के अनिल ने जीती है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का खाता भी नहीं खुला।

छह बार से बीजेपी के पार्षद थे अनिल स्वामी

नाराज वोटरों ने हराकर निर्दलीय को जिता दिया

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। नगर निगम चुनाव में इस बार कई इलाकों से ऐसे नतीजे समाने आए हैं जहां बड़े- बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। वार्ड 96 से भाजपा के छह बार से लगातार जीत हासिल कर पार्षद बनते रहे अनिल स्वामी को भाजपा से ही बागी होकर निर्दलीय जन उम्मीदवार अजीत निगम ने हरा दिया। स्वामी निर्वतमान मेयर आशा शर्मा के भाईहैं और 2012 में निर्विरोध चुनाव जीते थे।

पिछले निगम चुनाव में अजीत निगम मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। अनिल स्वामी से नेहरू नगर व अशोक नगर वार्ड के लोग इस काराण नारज थे कि वे जीत के बाद न तो लोगों से मिलते थे नही उनकी समस्याओं का निवारण कराते थे।

कुछ लोग उनके व्यवहार को लेकर भी नाराज थे। भाजपा के ही लोग आरोप लगाते थे कि जीत के बाद अनिल स्वामी अपना अधिकांश वक्त अक्सर कनाडा में बिताने अपने बेटे के पास बिताते थे। हांलाकि पूरे प्रदेश में भले ही भाजपा की आंधी चल रही थी लेकिन ऐसी आंधी के वक्त भाजपा के तीस साल से लगातार जीत हासिल करते आ रहे पार्षद का एक निर्दलीय के हाथों हार जाना साबित करता है कि अनिल स्वामी से क्षेत्र की जनता जबरदस्त ढंग से नाराज थी। अनिल स्वामी को चुनाव हराने वाले अजीत निगम पिछला चुनाव से थोडे से अंतर से हार गए थे। लेकिन हारने के बावजूद अजीत निगम ने जनता से नाता नहीं तोडा और हार के बावजूद एक पार्षद की तरह लोगों की मदद करते रहे। अजीत निगम को चुनाव लडाने में वार्ड 96 की जनता ने अहम भूमिका निभाई। अजीत निगम को जब इस बार भाजपा ने टिकट न देकर अनिल स्वामी को ही टिकट दे दिया तो क्षेत्र के लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित कर स्वतंत्र रूप से चुनाव लडने के लिए

कहा। अजीत निगम ने नेहरूनगर अशोक नगर एक-एक वोटर से व्यक्तिगत मुलाकात कर पिछले कुछ सालों में भाजपा पार्षद अनिल स्वामी द्वारा क्षेत्र को लेकर किए गए कार्यो की बाबत पूछा तो उन्हें लोगों की स्वामी के प्रति नाराजगी का पता चला। जबकि अजीत निगम ने वहीं क्षेत्र के लोगों के बीच पिछले पांच साल में अपने द्वारा किए गए काम से लोगों को इतना प्रभावित किया कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें क्षेत्र का पार्षद चुन लिया।

अजीत निगम प्रचार के दौरान मिले विशेष खबर मीडिया समूह के प्रधान संपादक विनीत कांत पाराशर से

निर्दलीय पार्षद चुने गए अजीत निगम ने नामांकन के बाद विशेष खबर मीडिया समूह के नेहरू नगर सेकेंड स्थित प्रशासनिक कार्यालय में आकर प्रधान संपादक विनीत कांत पाराशर से मुलाकात कर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किए और जीत का आशीर्वाद लेकर जीत का चुनाव की रणनीति तैयार की थी। विशेष खबर से बातचीत में अजीत निगम ने कहा था कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना पार्षद चुना तो सप्ताह के सात दिन और 24 घंटे जनता की सेवा में हाजिर रहेंगे।

यूपी में आंधी थी पर मेरठ-सहारनपुर मंडल में 26 पालिका में ही खिला कमल

संगठन और मंत्रियों की फौज का भी नहीं चला जादू

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। मेरठ-सहारनपुर मंडल में महापौर सीट को छोड़कर भाजपा का जादू नहीं चला। दोनों मंडलों में नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष की 90 सीटों में से भाजपा 64 सीटें हार गई। सिर्फ 26 सीटों पर ही भाजपा प्रत्याशी जीत पाए। बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जैसे शहरों में निर्दलीय प्रत्याशियों का जादू चला है। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बागपत ऐसे जिले हैं, जहां भाजपा सिर्फ एक-एक सीट पर सिमट गई। दोनों मंडलों में नगर निकायों में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें बुलंदशहर से मिली हैं। यहां कुल 17 नगर पालिका और पंचायतें हैं। इसमें से 9 चेयरमैन बीजेपी के बने हैं।

दो मंडलों में भाजपा की स्थिति देखिए

जनपद	कुल सीट	भाजपा जीती
सहारनपुर	11	3
मुजफ्फरनगर	10	1
शामली	10	2
गाजियाबाद	8	1
मेरठ	15	4
बागपत	9	1
हापुड़	4	2
बुलंदशहर	17	9
गौतमबुद्धनगर	6	3

दोनों मंडलों में मंत्री, सांसद, विधायकों की फौज

केंद्र सरकार में राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान केंद्र में मंत्री हैं। इनके अलावा गाजियाबाद से ही नरेंद्र कश्यप, मेरठ से सोमेंद्र तोमर और दिनेश खटीक, देवबंद से कुंवर बृजेश सिंह, बागपत से केपी मलिक, सहारनपुर से जसवंत सैनी भी राज्यमंत्री हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसदों की बात करें तो गाजियाबाद-नोएडा में एक-एक और मेरठ में दो हैं। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल बिजनौर जिले से हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल शामली, प्रदेश मंत्री डॉ. चंद्रमोहन और अमित वाल्मीकि बुलंदशहर, प्रदेश मंत्री बसंत त्यागी गाजियाबाद से हैं।

भाजपा के हारने की क्या है वजह?

पहली बार ऐसा हुआ, जब भाजपा में टिकट वितरण को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ। रुपए लेकर टिकट बांटने तक के खुले आरोप लगे। बुलंदशहर में भाजपा ने दो सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया, जो सालभर पहले ही दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए थे। इसे लेकर खुलकर विरोध किया। नोएडा की जेवर सीट पर भी चुनाव से चंद दिनों पहले भाजपा में शामिल हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। भाजपाई इसके खिलाफ हो गए। नतीजा ये रहा कि वो प्रत्याशी चौथे नंबर पर पहुंच गया। गाजियाबाद में लोनी, खोड़ा और मुरादनगर सीट भी भाजपा अंतर कलह की वजह से हार गई।

लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुला पत्र लिखकर सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि चेयरमैन का टिकट दो करोड़ रुपए में बेचने की साजिश हो रही है। इसी तरह जेवर सीट का टिकट 70 लाख रुपए में और औरंगाबाद नगर पंचायत का टिकट करीब 30 लाख रुपए में बेचने के आरोप भाजपा पदाधिकारियों पर लगे थे। कुल मिलाकर भाजपा के जिन पुराने कार्यकर्ताओं को चेयरमैन का टिकट नहीं मिला, वे बागी होकर चुनाव लड़े और भाजपा से बेहतर स्थिति में वोट पाए।

हालांकि ये भी सच है कि भाजपा उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल करने वाले ज्यादातर निर्दलीय भाजपा के ही बागी उम्मीदवार हैं। इससे ये आरोप तो साफ हो गए कि पार्टी ने सही ढंग से टिकटों का बंटवारा नहीं किया और पैसा लेकर टिकट बांटने के आरोप सही थे। हांलाकि दोनों मंडलों में बागी होकर चुनाव लड़ने और लड़ाने वाले वाले नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है लेकिन बागियों की जीत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जीतने वाले बागी पार्टी में शामिल कर लिए जाएंगे?

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक विनीतकांत पाराशर द्वारा विवेक पब्लिशर ए - 16, सेक्टर 7 नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से मुद्रित कराकर सैकेंड ए-288 नेहरुनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 202001 से प्रकाशित किया। संपादक-विनीतकांत पाराशर